PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 283 ● भिलाई, शुक्रवार 22 मई 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

नीति आयोग समर्थित 'मिशन कामयाबी' के तहत वर्चुअल रियलिटी और आधुनिक तकनीक से होगा शिक्षण

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 'कामयाबी वेन' को दिखाई हरी झंडी : दूरस्थ गांवों के विद्यार्थियों तक पहुंचेगी डिजिटल शिक्षा की नई रोशनी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के अंतर्गत कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के ग्राम कुशहा में आयोजित चौपाल के दौरान नीति आयोग द्वारा वित्तपोषित 'मिशन कामयाबी' के तहत संचालित 'कामयाबी वेन' को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस पहल के माध्यम से दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों तक आधुनिक डिजिटल शिक्षा और तकनीकी आधारित सीखने के अवसर पहुंचाए जाएंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और सीखने के अनुभव में सकारात्मक बदलाव आएगा।

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि गांवों और दूरस्थ

क्षेत्रों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक तकनीक का समान अवसर मिले। उन्होंने कहा कि दौर ज्ञान, नवाचार और तकनीक का है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी डिजिटल संसाधनों और नई शिक्षण पद्धतियों से जोड़ना आवश्यक है, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें।

उल्लेखनीय है कि 'कामयाबी वेन' के माध्यम से विद्यार्थियों को वर्चुअल रियलिटी एवं ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक आधारित शिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। यह वेन विज्ञान, गणित, तकनीकी अवधारणाओं और अन्य विषयों को अधिक रोचक, अनुभवात्मक और व्यवहारिक तरीके से समझाने में सहायक होगी। इससे विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता, तकनीकी जागरूकता तथा बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में सुधार आने की संभावना है। मुख्यमंत्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि यह अभिनव पहल दूरस्थ गांवों के विद्यार्थियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी तथा उन्हें विज्ञान, डिजिटल तकनीक और आधुनिक शिक्षा से सरल एवं प्रभावी ढंग से जोड़ने का माध्यम बनेगी।

'तेंदूपत्ता संग्राहकों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री, महुआ पेड़ के नीचे लगाई चौपाल'

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सूरजपुर प्रवास के दौरान रामानुजनगर प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण फड़ पटना का निरीक्षण कर तेंदूपत्ता संग्राहकों से आत्मीय संवाद किया। मुख्यमंत्री साय ने तेंदूपत्ता संग्रहण कार्यों का जायजा लेते हुए संग्राहकों की समस्याओं, आजीविका और मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली तथा वनाधारित अर्थव्यवस्था से जुड़े परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के आगमन पर तेंदूपत्ता संग्राहकों ने आत्मीय स्वागत करते हुए तेंदूपत्ता और तेंदू फलों से निर्मित विशेष माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक भूलन सिंह मरावी तथा वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा का भी सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने संग्राहकों के श्रम और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि वनाधारित आजीविका से जुड़े लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण शक्ति हैं और उनके जीवन में समृद्धि लाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महुआ पेड़ की छांव में चौपाल लगाकर संग्राहकों से सीधा संवाद किया और कहा कि सरकार स्वयं लोगों का हालचाल जानने गांव-गांव पहुंच रही है।

संक्षिप्त समाचार

मप्र के उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने पटना में बिहार के डिजिटल स्वास्थ्य मॉडल की जानकारी ली

भोपाल। मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बुधवार को बिहार के सरकारी अस्पतालों में लागू डिजिटलीकरण व्यवस्था के बारे में जानकारी ली।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार शुक्ला ने पटना में स्वास्थ्य विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करके विशेष रूप से 'भव्या' पोर्टल के संचालन, उसकी कार्यप्रणाली तथा आमजन को मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि यह पोर्टल स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुगम और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सांसद सायोनी घोष का सिर कलम करने पर एक करोड़ का रखा ईनाम

सिकंदराबाद। पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद सायोनी घोष का सिर कलम करने वाले को एक करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा करने वाले उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता और सिकंदराबाद नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. प्रदीप दीक्षित अब अपने बयान से बैकफुट पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो वायरल होने और चौतरफा घिरने के बाद उन्होंने बुधवार शाम एक नया वीडियो जारी कर अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बुलंदशहर के सिकंदराबाद में करीब पांच दिन पहले आयोजित एक धर्म ध्वज यात्रा के दौरान डॉ. प्रदीप दीक्षित ने यह भड़काऊ बयान दिया था। वीडियो सामने आने के बाद राजनीति गर्मा गई। टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया।

पुलवामा आतंकी हमले के मास्टर माइंड हमजा बुरहान की हत्या

- पीओके में अज्ञात हमलावर ने गोली मारी

नई दिल्ली। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की हत्या कर दी गई है। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और तिबंधित संगठन 'अल बद्र' के प्रमुख कमांडर आतंकी हमजा बुरहान को पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में अज्ञात हमलावर ने गोली मारी। हमले में आतंकी हमजा बुरहान की मौत हो गई है। हमजा बुरहान की हत्या के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। पुलवामा का रहने वाला यह मोस्ट वांटेड आतंकी पिछले 7 सालों से पाकिस्तान में रह रहा था। सूत्रों के मुताबिक ओके में अज्ञात हमलावरों ने हमजा बुरहान को निशाना बनाकर कई गोलियां चलाईं। हमले के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भारत सरकार ने 2022 में हमजा बुरहान को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया था। पुलवामा आतंकी हमला भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक और भीषण आतंकवादी हमलों में से एक है, जो 14 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के लेथपोरा में हुआ था। इस आत्मघाती आतंकी हमले में भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ के लगभग 2,500 जवान 78 वाहनों के काफिले में जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। दोपहर करीब 3:15 बजे, विपरीत दिशा से आ रही एक कार ने जवानों को ले जा रही बस में टक्कर मार दी। कार में करीब 300 किलोग्राम से अधिक आरडीएक्स और अन्य विस्फोटक भरे हुए थे। टक्कर होते ही एक भयानक धमाका हुआ, जिससे बस पूरी तरह नष्ट हो गई। इस हमले को स्थानीय कश्मीरी आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार ने अंजाम दिया था। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन बालाकोट अंजाम दिया था। पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के अड्डे को तबाह कर दिया था। हमजा बुरहान पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं में शामिल था। वह खुद को पाकिस्तान में टीचर बताता था। साथ ही 2019 के बाद से कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा था। वह पीओके के इलाके में कई आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग दे रहा था। साथ ही बॉर्डर इलाके में वह आतंकियों को घुसपैठ कराने में मदद करता था।

देश में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध : सरकार

नयी दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने लोगों को एक बार आश्वस्त किया है कि देश में एलपीजी से लेकर पेट्रोल तथा डीजल सहित सभी ऊर्जा संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता है और उन्हें हड़बड़ी में खरीदारी से बचना चाहिए। पश्चिम एशिया की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर देश में एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है लेकिन सरकार देश में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि देश में गैस वितरण एजेन्सियों और तेल वितरण कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग 99 प्रतिशत हो गयी है और कालाबाजारी रोकने के लिए शुरू की गयी सत्यापन कोड प्रणाली से डिलीवरी 96 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। पिछले तीन दिनों में एक करोड़ 34 लाख गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की गयी।

इसके अलावा 58 हजार से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन वापस कर दिये हैं।

कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए पिछले तीन दिनों में देश में 500 छापे मारे गये हैं।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की ओर से बताया गया कि पश्चिम एशिया में सभी भारतीय पोत और उन पर सवार नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटे में किसी प्रकार की कोई अवांछित घटना नहीं हुई है।

कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम और कारपूलिंग की व्यवस्था

गर्मी की छुट्टियों के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने चल रही गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कई उपाय लागू किए हैं. इनमें मामलों की वर्चुअल सुनवाई, कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम और कारपूलिंग की व्यवस्था शामिल है. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इन उपायों का मकसद संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना और न्यायिक कामकाज को सुचारू रूप से चलाना है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के मार्गदर्शन में जारी परिपत्र के अनुसार, अवकाश अवधि में मामलों की सुनवाई सामान्यतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा सकेगी. इसका उद्देश्य अनावश्यक आवागमन कम करना और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना बताया गया है.

परिपत्र में हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका के कर्मचारियों को सप्ताह में अधिकतम दो दिन वर्क फ्रॉम होम सुविधा देने का भी प्रस्ताव रखा गया है. इसके लिए यह शर्त रखी गई है कि कार्यालय में कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति बनी रहे ताकि कामकाज प्रभावित न हो. घर से कार्य करने वाले कर्मचारियों को फोन और अन्य आधिकारिक माध्यमों से उपलब्ध रहना होगा.

रजिस्ट्रार जनरल ने दी जानकारी: रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि यह निर्देश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने जारी किए हैं. ये निर्देश भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्मियों की छुट्टियों (2026) के लिए जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां 18 मई से शुरू हो गई हैं और 15 जून तक जारी रहेंगी.सर्कुलर के मुताबिक, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान हाई कोर्ट में मामलों की सुनवाई मुख्य रूप से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए की जाएगी।

जो वकील किसी अनिवार्य कारण से वर्चुअल रूप से शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने की अनुमति दी जाएगी।

चिरमिरी में श्रीराम कथा का तीसरा दिन रहा भक्तिमय

जगद्गुरु रामभद्राचार्य के प्रवचनों से गूंजा कथा पंडाल

चिरमिरी। गोदरीपारा स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित भव्य श्रीराम कथा महोत्सव के तीसरे दिन श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला। कथा पंडाल में हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति से पूरा वातावरण राममय हो गया। जय श्रीराम के उद्घोष, भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों से श्रद्धालु भावविभोर नजर आए।

कथा व्यास पद्मविभूषित जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने अपने ओजस्वी एवं भावपूर्ण प्रवचनों में भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन, धर्म पालन और मर्यादा के महत्व का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि रामकथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मानव जीवन को सही दिशा देने वाली प्रेरणा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपने जीवन में प्रेम, सेवा, त्याग और संस्कारों को अपनाने का आह्वान किया।

माता कौशल्या और श्रीराम के बाल रूप का भावपूर्ण प्रसंग: गद्गुरु रामभद्राचार्य ने भगवान श्रीराम के जन्म और बाल्यकाल से जुड़े प्रसंगों का अत्यंत भावुक वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जब भगवान श्रीराम माता कौशल्या के समक्ष धनुष-बाण धारण किए किशोर अवस्था में प्रकट हुए, तब माता कौशल्या ने कहा कि यदि वे इसी रूप में रहेंगे तो लोग उन्हें उनकी माता नहीं मानेंगे। इस पर श्रीराम ने कहा कि वे रावण वध के उद्देश्य से अवतरित हुए हैं। किंतु माता कौशल्या ने इच्छा व्यक्त की कि वह उन्हें

एक बालक की तरह गोद में खिलाकर बड़ा होते देखना चाहती हैं। इसके बाद श्रीराम बाल रूप धारण कर सामान्य बालक की तरह आंगन में किलकारियां भरने लगे और अयोध्या में बधाइयों का तांता लग गया। उन्होंने माता कौशल्या के अपहरण से जुड़ा रोचक प्रसंग भी सुनाया। कथा के अनुसार रावण ने भगवान महादेव की पूजा करने जा रही कौशल्या का अपहरण कर उन्हें एक बक्से में बंद कर समुद्र में बहा दिया था। बाद में वह बक्सा सरयू नदी के माध्यम से अयोध्या पहुंचा, जहां अयोध्यावासियों ने उसे राजा दशरथ को सौंपा। बक्सा खोलने पर उसमें से कौशल्या निकलीं। जगद्गुरु ने बताया कि कौशल्या दंडकारण्य के राजा भानुप्रताप और माता संध्या की पुत्री थीं। राजा दशरथ ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उनके परिवार तक पहुंचाया और आगे चलकर दोनों का विवाह हुआ।

श्रवण धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म: कथा के दौरान जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि श्रवण सर्वधर्म मान्य तपोधना अर्थात श्रवण धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। उन्होंने छत्तीसगढ़ को भगवान श्रीराम का ननिहाल बताते हुए कहा कि पूरे प्रदेश को राममय बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भांचा को विशेष सम्मान दिया जाता है और यहां मामा द्वारा भांचा के चरण स्पर्श करने की परंपरा इस भूमि की महान संस्कृति को दर्शाती है।

मरीज के ईलाज में लापरवाही

श्री संकल्प मिशन हॉस्पिटल छुरा का लाइसेंस 30 दिन के लिये निलंबित

छुरा/गरियाबंद। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा छुरा स्थित निजी श्री संकल्प छत्तीसगढ़ मिशन हॉस्पिटल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुये अस्पताल का अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से 30 दिनों के लिये निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई अस्पताल में उपचार संबंधी गंभीर अनियमितताओं, बिना अनुमति सीटी स्कैन संचालन तथा बिना विशेषज्ञ चिकित्सक के डिलीवरी कराये जाने के मामले में की गई है।

जानकारी के अनुसार स्थानीय मीडिया एवं दैनिक समाचार पत्र में इस अस्पताल में ईलाज के नाम पर चल रही गंभीर अनियमितताओं के संबंध में खबर का प्रकाशन किया गया था। इन खबरों को संज्ञान में लेते हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

अधिकारी कार्यालय द्वारा 7 सदस्यीय जांच दल गठित कर मामले की जांच कराई गई थी। 9 दिनों तक चला झूठ ईलाज : हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की जान का खतरा

जांच दल द्वारा अस्पताल के रिकॉर्ड में मरीज के उपचार से संबंधित अनियमितताएं पाई गईं। साथ ही 12 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया था। अस्पताल प्रबंधन द्वारा 28 अप्रैल 2026 को जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन जांच टीम ने जवाब को अस्पष्ट एवं विरोधाभासी बताते हुए असंतोषजनक माना। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अस्पताल में मरीजों के उपचार में समुचित गंभीरता की कमी परिलक्षित हुई है। इसके अलावा बिना अनुमति एवं बिना अनुबंधित स्त्री रोग विशेषज्ञ के 24 घंटे सामान्य और सिजेरियन डिलीवरी कराई जा रही थी, जिससे हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की जान को खतरा बढ़ने की आशंका जताई गई। छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 के तहत कार्रवाई करते हुये अस्पताल का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है।

बिना अनुमति चल रहा था सीटी स्कैन सेंटर

जांच में यह भी सामने आया कि श्री संकल्प छत्तीसगढ़ मिशन हॉस्पिटल में सीटी स्कैन मशीन का संचालन बिना वैधानिक अनुमति के किया जा रहा था। आदेश के अनुसार अस्पताल में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत पंजीयन के बिना तथा बिना किसी अनुबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर के सीटी स्कैन किया जा रहा था। इतना ही नहीं, बिना अर्हताधारी चिकित्सक की उपस्थिति के मरीजों की जांच कर रिपोर्ट भी जारी की जा रही थी। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया।

उत्तर भारत में सूरज उगल रहा आग यूपी के बांदा में पारा 48 पर पहुंचा

नई दिल्ली। देश के उत्तर भारत में भीषण गर्मी जारी है। उत्तर भारत आग की भट्टी में तब्दील हो गया है। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री से पार है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। लू की तेज हवाएं तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को देश के करीब 50फीसदी हिस्से में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, विदर्भ और ओडिशा जैसे राज्यों में भारी

गर्मी पड़ रही है। यूपी के बांदा में सबसे ज्यादा तापमान 48.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है।

वहीं सबसे ज्यादा गर्मी यूपी, मध्य प्रदेश और विदर्भ (महाराष्ट्र) के इलाकों में पड़ रही है। बांदा, खजुराहो, वर्धा, रोहतक और नागपुर जैसे शहर इस समय सूरज की तपिश में जल रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मई के अंत तक गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं। उत्तर-पश्चिम भारत, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान बना रहने की संभावना है। लू की स्थिति भी जारी रहेगी।

इस भीषण गर्मी में दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल है। खेतों में काम करने वाले किसान, मजदूर और सड़क पर काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

सोने-चांदी के व्यापार पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंधों के खिलाफ कांग्रेस ने किया धरना-प्रदर्शन

बलौदाबाजार। सोने-चांदी के व्यापार पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जा रहे अनावश्यक प्रतिबंधों एवं जटिल नियमों के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना-प्रदर्शन एवं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यम के दौरान व्यापारियों, स्वर्णकारों, छोटे व्यवसायियों एवं आम नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। व्यापारियों ने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियों एवं लगातार बढ़ती प्रशासनिक जटिलताओं के कारण सोने-चांदी के व्यापार से जुड़े छोटे दुकानदारों, कारीगरों एवं श्रमिकों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कांग्रेसजनों ने कहा कि सोने-चांदी का व्यापार केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की रोजी-रोटी का माध्यम है। केंद्र सरकार द्वारा थोपे जा रहे नियमों से छोटे व्यापारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, वहीं पारंपरिक स्वर्णकारी कार्य से जुड़े कारीगरों का रोजगार भी प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही पेट्रोल-डीजल एवं खाद्य सामग्री के लगातार बढ़ते दामों को लेकर भी केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की गई। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि महंगाई ने आम जनता, किसानों, मजदूरों एवं मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। डीजल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर परिवहन, खेती-किसानी एवं रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर पड़ रहा है, जिससे हर वर्ग परेशान है। धरना-प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि व्यापारियों एवं कारीगरों के हितों को ध्यान में रखते हुए जनविरोधी फैसलों को तत्काल वापस लिया जाए तथा सोने-चांदी की खरीदी पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों को समाप्त कर व्यापार को सरल एवं सुरक्षित बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएं। साथ ही बढ़ती महंगाई, डीजल एवं खाद्य सामग्री के बढ़े दामों को नियंत्रित करने की मांग भी उठाई गई। कार्यक्रम के पश्चात राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु के नाम ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में व्यापारी वर्ग, कारीगरों एवं आम जनता की समस्याओं से अवगत कराया गया। कार्यक्रम मे प्रमुख रूप से कांग्रेस कमिटी की जिलाध्यक्ष सुमित्रा धृतलहरे, कृषक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष परमेश्वर यदु, पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश यदु, जिला कोषाध्यक्ष हेमचंद केसरवानी शहर कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष प्रवीण सेन ग्रामीण अध्यक्ष दीपक साहू, जिला महामंत्री लखेश साहू, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल, अविनाश मिश्रा, मंडल अध्यक्ष संतोष साहू, दीनदयाल साहू, शाश्वत यादव, जिला उपाध्यक्ष लक्ष्म चंद्र प्रकाश साहू,, इंटक जिला अध्यक्ष चीतेन्द्र वर्मा, शहर महामंत्री भेनू तिलक कन्नौजे, प्रसाद साहू, महामंत्री मंजू प्रसाद साहू, आयुष भाटपहरी, शहर महामंत्री नीरज बांधे, मोहन साहू, गणेश शंकर साहू, अभिषेक पटेल, नेता प्रतिपक्ष सलमान शेख, पार्षद, अर्जुन सेन डिगेश्वरी रविंद्र नामदेव, सहित समस्त कांग्रेस जन उपस्थित रहे।

जिले में 25 मई तक मनाया जाएगा जनजातीय गरिमा उत्सव, 46 गांव में लगाए जाएंगे योजना संतृप्तिकरण शिविर

बलौदाबाजार। जिले में 18 से 25 मई तक जनजातीय गरिमा उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर जन भागीदारी सबसे दूर, सबसे पहले अभियान भी चलाया जाएगा। इसके तहत जिले के 46 जनजातीय बाहुल्य गाँव में योजनाओं के संतृप्तिकरण हेतु विशेष शिविर लगाए जाएंगे। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने समय -सीमा की बैठक में शिविर आयोजन के सम्बंध में अधिकारियो को जरुरी निर्देश दिये। अभियान के तहत 18 मई को शुभारम्भ,19 से से 25 मई तक संतृप्तिकरण शिविर लगाए जाएंगे जिसमें, स्वास्थ्य जांच भी होगा। अधिकारी एवं आदि कर्मयोगी द्वारा ग्राम भ्रमण, 21 से 23 मई तक जनसुनवाई, 24 एवं 25 मई को दस्तावेजीकरण होगा। कलेक्टर शर्मा ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि 6 माह से अधिक समय तक लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये मुहीम चलाएं और 15 जुलाई तक पूरा करें। इसके पश्चात् कोई भी प्रकरण 3 माह से अधिक लंबित नहीं होना चाहिए। उन्होंने सीमांकन आवेदन के निराकरण के लिये आरआई अनुसार मैपिंग कर आवंटित करने तथा समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिये।उन्होंने पटवारी और सचिव को आवंटित प्रभार के गांव में उपस्थिति का दिन समय पंचायत कार्यालय में चस्पा करने कहा ताकि लोगों को उनके कार्यालय में उपस्थिति की जानकारी रहे। कलेक्टर ने पेट्रोल पम्प में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति एवं वितरण हेतु एसडीएम एवं तहसीलदारो को नियमित जांच करने के निर्देश दिये।

आगामी खरीफ सीजन हेतु समितियों में खाद बीज का पर्याप्त भण्डारण तथा किसानों को नैनो यूरिया व नैनो डीईपी के उपयोग के लिये प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने विभिन्न सड़कों के निर्माण की समीक्षा करते हुए बारिश से पहले निर्माण कार्य पूर्ण करने कहा। सड़क डिवाइडर में कट होने पर एजेंसी होंगे जिम्मेदार- शहरों में सड़क में बनाए जा रहे डिवाइडर में जगह-जगह कट के कारण दुर्घना की प्रबल आशंका को देखते हुए कलेक्टर शर्मा ने मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि डिवाइडर में किस स्थान पर कट देना है उसके लिये समिति गठित कर उसके निर्णय अनुसार ही उसी स्थान पर कट दिया जाए। इसके अतिरिक्त अन्य स्थान पर कट होने और दुर्घटना होने पर सम्बंधित एजेंसी को भी पक्षकार बनाया जाएगा। बैठक में सीईओ जिला पंचायत सुदिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर अभिषेक गुप्ता, निशा नेताम मड़ावी सहित एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

सुशासन तिहार में वृद्धजनों को मिला सहारा

गरियाबंद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजित सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत छुरा विकासखंड के ग्राम कनसिंघी में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धजनों को छड़ी आदि सामग्री प्रदान कर सहयोग दिया। बढ़ती उम्र के साथ चलने-फिरने में होने वाली कठिनाइयों एवं सहारे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्राम कनसिंघी निवासी 76 वर्षीय भगवान दास वैष्णव एवं 79 वर्षीय बिसाहू राम को छड़ी प्रदान की गई। शिविर में कलेक्टर बीएस उइके, पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चंद्राकर ने दोनों वृद्धजनों को छड़ी प्रदान कर शुभकामनाएं दीं। सहायक सामग्री प्राप्त कर दोनों हितग्राहियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के प्रति आभार जताया। सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है। जिससे आमजन को समय पर सहायता एवं संबल प्राप्त हो रहा है।

भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण खाद की भारी संकट : तारिणी चंद्राकर

धमतरी। प्रदेश में खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले ही प्रदेश भर में रासायनिक खाद यूरिया और डीएपी की भारी किल्लत को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कहा कि साय सरकार की गलत खाद नीति और कुप्रबंधन ने धन्हा धमतरी कहे जाने वाले जिले के किसानों को संकट में डाल दिया है। जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई खाद वितरण नीति पूरी तरह से किसान विरोधी है। नई व्यवस्था में खाद का कोटा कम कर दिया गया है और टोकन की अनिवार्यता लागू कर दी गई है, जिससे प्राथमिक सेवा सहकारी समितियों में किसानों को घंटों कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ नेताओं ने भी स्पष्ट किया है कि जो खाद किसानों को अप्रैल.मई की शुरुआत में मिल जाया करती थी, वह मई का आधा महीना बीतने के बाद भी समितियों से नदारद है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने जमीनी हकीकत उजागर करते हुए कहा कि

सरकारी सोसायटियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। खाद की उपलब्धता जरूरत के हिसाब से लगभग शून्य है, जबकि निजी दुकानों में वही खाद ऊंचे और मनमाने दामों पर बेची जा रही है। बिचौलियों और कालाबाजारियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण वे खुलेआम किसानों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान न केवल खाद संकट बल्कि राज्य में गहराए ईंधन डीजल.पेट्रोल के संकट से भी दो.चार हो रहे हैं। ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों के लिए डीजल न मिलने से खेतों की तैयारी ठप पड़ गई है। सरकार द्वारा ईंधन की सीमा लिमिट तय करने से ग्रामीण क्षेत्रों में अफरा-तफरी का माहौल है। हमारी मांग है की किसानों को परेशानी में डालने वाली नई खाद नीति और टोकन व्यवस्था को तत्काल निरस्त कर पुरानी व्यवस्था बहाल की जाए, खरीफ सीजन की मांग के अनुरूप सभी प्राथमिक सहकारी समितियों में डीएपी और यूरिया का पर्याप्त भंडारण युद्ध स्तर पर सुनिश्चित किया जाए, निजी विक्रेताओं द्वारा की जा रही खाद की कालाबाजारी और ओवर-रेटिंग पर तुरंत कानूनी कार्रवाई हो, कृषि कार्य के लिए किसानों को बिना किसी सीमा लिमिट के प्राथमिकता के आधार पर डीजल उपलब्ध कराया जाए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर ने साय सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि एक सप्ताह के भीतर सोसायटियों में पर्याप्त खाद की आपूर्ति शुरू नहीं की गई और खाद नीति में सुधार नहीं हुआ, तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मिलकर पूरे ब्लॉक और जिला स्तर पर चक्का जाम और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

ड्यूटी के दौरान दुर्घटना से निधन, पुलिस कर्मियों को शहीद का दर्जा देने की मांग

धमतरी। नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा को लेकर हमेशा अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहने वाले पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के दौरान दुर्घटना या अन्य कारणों से निधन होने पर उन्हें शहीद का दर्जा दिये जाने की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, युवा गृहमंत्री विजय शर्मा, डीजीपी अरूण देव गौतम से जिले के नागरिकों ने की है। क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर ड्यूटी में तैनात कोतवाली थाना में पदस्थ कर्मियों का सिहावा चौक में बीति देर रात गश्त के दौरान एक अज्ञात वाहन ने जबरदस्त टक्कर मारी जिससे प्रधान आरक्षक की स्थल पर ही मौत हो गई और उनके साथ बैठे नगर सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गये जिसे एक निजी अस्पताल में ले जाया गया था। उसकी गंभीर हालत को देखकर रायपुर रिफर कर दिया गया। ड्यूटी के दौरान गश्त कर रहे दोनों कर्मियों को जिस पिकअप वाहन ने ठोकर मारी है, उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह दुर्घटना विभाग के लिये एक जबरदस्त वज्रपात के रूप में घटित हुआ है। इसे लेकर शहर के नागरिकों ने प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों से उक्त प्रधान आरक्षक विजय बैरागी को शहीद का दर्जा देने की मांग करते हुए शासन से मांग की है कि ड्यूटी के दौरान दुर्घटना से निधन हुए पुलिस कर्मियों को शहीद का

दर्जा दिया जाये। कोतवाली थाना में पदस्थ उक्त प्रधान आरक्षक विजय बैरागी अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से सक्रिय रहा करते थे और विभाग के साथ साथ शहर के नागरिकों में भी उनकी एक अच्छी पकड़ थी। अपराधों को लेकर वे पूरी तरह सजगता के साथ काम किया करते थे। घटना के दिन भी वे अपनी कार्यशैली के मुताबिक देर रात गश्त कर रहे थे। जब वह सिहावा चौक पहुंचे तो तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप वाहन ने उनकी वाहन को अपनी चपेट में ले लिया जिससे प्रधान आरक्षक विजय बैरागी को गंभीर चोटें आई। इससे पहले कि उन्हें तत्कालिक उपचार मिलता, घटना स्थल पर ही उनका प्राण पखेरू उड गये जबकि उनका साथी नगर सैनिक को भी भारी चोट पहुंची है। उन्हें धमतरी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन उनकी हालत नाजुक थी जिसे देखते हुए उन्हें रायपुर रिफर कर दिया गया। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक घायल नगर सैनिक के स्थिति का पता नहीं चल पाया है। लेकिन इस दुर्घटना से पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधान आरक्षक के निधन की खबर से शहरवासी स्तब्ध हैं।

उन्होंने इस दुर्घटना पर खेद व्यक्त करते हुए मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शासन से ड्यूटी के दौरान हादसे में मृत प्रधान आरक्षक को शहीद का दर्जा दिये जाने की मांग की है। साथ ही इन्होंने यह भी मांग की है कि भविष्य में जितने भी पुलिस कर्मियों की मौत ऐसे हादसे में हो, उन्हें भी शहीद का दर्जा दिया जाये।

ई-कॉमर्स के विरोध में मेडिकल बंद का दिखा असर

धमतरी। धमतरी में ऑनलाईन दवाईयों की बिक्री के विरोध में मेडिकल एसोसियेशन ने एक दिवसीय बंद का ऐलान कर अपना विरोध दर्ज कराया। जिले भर के लगभग 500 से अधिक मेडिकल संचालक हड़ताल में शामिल रहे जिससे आम लोगों को दवाईयां लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेडिकल संघ का आरोप है कि ऑनलाईन प्लेटफार्म में बिना डॉक्टर के पर्ची के दवाईयां बेची जा रही है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक साबित हो सकता है। फिलहाल मेडिकल संघ का यह विरोध आगे कितना असर दिखाता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। जिला मेडिकल संघ के सचिव सतराम वासानी ने बताया कि ऑनलाईन दवा बिक्री को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हमारे द्वारा किया जा रहा है जिसे लेकर कुछ दिनों पूर्व हमारे द्वारा जानकारी भी दे दी गई थी बावजूद इसके गंभीर परिस्थिति के लिये रेडक्रॉस एवं नर्सिंग होम में दवाईयां उपलब्ध हैं।

केमिस्ट हड़ताल के दौरान आवश्यक औषधियों की उपलब्धता के लिये जिला प्रशासन सतर्क

बलौदाबाजार। ऑनलाइन औषधियों की बिक्री के विरोध स्वरूप जिला औषधि विक्रेता संघ बलौदाबाजार द्वारा 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जिले में आम नागरिकों को आवश्यक औषधियों एवं स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जिले में संचालित समस्त जनऔषधि केन्द्रों (पीएमबीजेएके), धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स, शासकीय चिकित्सालयों, नर्सिंग होम्स एवं अन्य औषधि वितरण केन्द्रों के माध्यम से आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि आमजन एवं मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा दवा विक्रेता संघ को प्रस्तावित विरोध कार्यम के दौरान जनहित, रोगी सेवा एवं आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक दवाओं एवं स्वास्थ्य उत्पादों की उपलब्धता बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने कहा गया है। जिन मरीजों को नियमित दवाओं की आवश्यकता होती है, वे चिकित्सकीय परामर्श अनुसार आवश्यक दवाएं पूर्व में प्राप्त कर सुरक्षित रखें। आपातकालीन स्थिति में शासकीय अस्पतालों, जनऔषधि केन्द्रों।

चारभाठा में लगा जन समस्या निवारण शिविर, समास्याओं पर त्वरित कार्यवाही

सरायपाली। सरायपाली विकास खंड के ग्राम चारभांटा में सुशासन तिहार के तहत जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन हुआ जिसमे कुल 1066 आवेदन प्राप्त हुआ। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं एवं मांगों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की गई शिविर मे मुख्यातिथि के रूप मे सांसद रुपकुमारी चौधरी शामिल हुई। शिविर मे उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप राज्य में सुशासन व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है तथा योजनाओं का लाभअंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने शासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सुशासन शिविरों के माध्यम से प्रशासन सीधे गांवों तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है, जिससे ग्रामीणों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं शासन की योजनाएं अब सीधे गांव-गांव तक

पहुंच रही है तथा पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल रहा है। कुमारी भास्कर ने कहा कि जनसमस्या निवारण शिविर शासन और जनता के बीच सेतु का कार्य कर रहे हैं। जिससे ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही त्वरित समाधान उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। शासन का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसी तरह अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी ग्रामीणों को शासन की योजनाओं के प्रति जागरूक रहने तथा योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। शिविर के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गोदभराई व अन्नप्राशन संस्कार का कार्यक्रम आयोजन किया गया यह संस्कार अतिथियों के द्वारा सम्पन्न हुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया गया तथा ग्रामीणों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।

शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित होकर अपनी समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन किट प्रदान किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 'अंत्योदय' के संकल्प के साथ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक शासन की योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा निरंतर प्रयास है कि जनता को अपने कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े और शासन स्वयं उनके द्वार तक पहुंचे। सेवा, संवेदनशीलता और सुशासन के माध्यम से हम एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहां विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे और जनविश्वास निरंतर मजबूत हो। इस अवसर पर उक्त कार्यक्रम में मुख्यअतिथि के रूप मे लोकसभा महासमुंद की सांसद रूप कुमारी चौधरी शामिल हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष मोगरा पटेल, सभापति जिला पंचायत कुमारी भास्कर, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, जनपद उपाध्यक्ष धर्मेंद्र मुकेश चौधरी, सभापति उद्धव नन्द सहित जनप्रतिनिधि गण, भाजपा कार्यकर्तागण, अधिकारी-कर्मचारी, मातृशक्ति एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

जिपं सभापति के पहल से गौरव ग्राम खरेंगा को मिली पानी टैंकर की सौगात

धमतरी। जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत गौरव ग्राम खरेंगा में लंबे समय से बनी पेयजल समस्या को ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत सभापति मोनिका ऋषभ देवांगन के विशेष प्रयासों से 15वें वित्त आयोग की राशि से पानी टैंकर प्रदान किया गया। ग्रामवासियों की सुविधा हेतु उपलब्ध कराए गए इस पानी टैंकर का विधिवत लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। लोकार्पण अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित जिला पंचायत सभापति मोनिका देवांगन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी

जिम्मेदारी है। गर्मी के मौसम में ग्रामीणों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए 15वें वित्त आयोग की राशि का सदुपयोग करते हुए ग्राम खरेंगा के लिए पानी टैंकर उपलब्ध कराया गया है। इससे गांव के जरूरतमंद परिवारों को समय पर पेयजल उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी तथा पानी की समस्या से काफी हद तक राहत प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सड़क, पानी, बिजली एवं अन्य जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। जनपद सदस्य गीतेश्वरी साहू ने अपने संबोधन में कहा कि ग्राम खरेंगा में पानी की समस्या को लेकर लगातार मांग उठाई जा रही थी। जिला पंचायत सभापति मोनिका देवांगन द्वारा गंभीरता से पहल करते हुए पानी टैंकर उपलब्ध कराया गया है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने इसके लिए जिला पंचायत सभापति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जनहित से जुड़ा सराहनीय कार्य है। वहीं ग्राम सरपंच नीलम अदिल ने कहा कि गर्मी के दिनों में गांव में पेयजल समस्या अधिक बढ़ जाती थी, जिससे ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पानी टैंकर मिलने से अब जरूरत के समय गांव में पेयजल उपलब्ध कराने में सुविधा होगी। उन्होंने ग्राम पंचायत एवं समस्त ग्रामवासियों की ओर से जिला पंचायत सभापति मोनिका देवांगन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। मोनिका देवांगन ने ग्रामवासियों को पानी टैंकर की सौगात मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान एवं विकास कार्यों का विस्तार ही उनका प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने ग्रामीणों से पानी का संरक्षण एवं सदुपयोग करने की अपील भी की। इस अवसर पर उपसरपंच डिसेन्ट साहू, पूर्व सरपंच मोहन साहू, पूर्व सरपंच अमेरिका ध्रुव, ग्राम सचिव मेकूराम निषाद, ग्राम पंचायत के पंचगण, स्थानीय नागरिक तरुण साहू, भगवती विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

जगदीश चौहान बने फूलझर राज गांडा समाज के अध्यक्ष

सरायपाली। नया संगठन फूलझर राज कल्याण समिति का गठन सर्व समिति बनाया गया कई पदाधिकारीगण जो पुराने संघ मे थे उन्होने सामुहिक इस्तीफा देकर इस संगठन को आगे बढाने का संकल्प लिया सुनियोजित ढ़ंग से चलाने के लिए पदाधिकारी भी मनोनीत किये गये जिसमे संरक्षक के रूप मे पंचराम चौहान संयोजक चम्पत लाल चौहान फूलझर अध्यक्ष जगदीश चौहान उपाध्यक्ष पद के लिए 4 सदस्य मनोनीत किये गए जिसमे नृराधन सुरजाल अतंराम नंद शत्रुधन चौहान एंव उतम दीप है सचिव पद के लिए सुन्दर लाल चौहान एंव अशिवनी छत्रे संगठन मंत्री धनीराम चौहान राम प्रसाद चौहान कार्यकारिणी सदस्य के रूप मे राजकुमार बिषरा मोती लाल चौहान गोसाई राम मोहन लाल तांडी सुरेश चौहान करूणाकर तांडी दुर्योधन चौहान बिहारी चौहान एंव परमानन्द चौहान है। उपरोक्तपदाधिकारियों के द्वारा यह संकल्प लिया गया की समाज के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा समाज मे जगह-जगह लोग रोटी बेटी के नाम पर जुरबना वसूल किया जा रहा है उस पर भी रोक लगाकर बहु बेटियों को पुरा सम्मान दिया जाएगा ऐसे अनेक विषयों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा कर मिटिंग के लिए 31 मई को रखी गई है जिसमें सरायपाली बसना पिथौरा के समस्त गांडा समाज के कर्मचारी गण एंव समाज प्रमुख किसान बेरोजगार एंव जनप्रतिनिधि से आग्रह है की अधिक से अधिक संख्या मे आकर समाज की दिशा व दसा को उज्जवल बनाने का संकल्प लेवें।

संक्षिप्त समाचार

अवमानना के बढ़ते प्रकरणों पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर सूर्यकांत सीजेआई

रायपुर। हैदराबाद में आयोजित हाल ही में न्यायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुर्यकांत ने राज्य सरकारों द्वारा हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों पर उनके विरुद्ध दिये जा रहे फैसले का पालन करने में टाल मटोल करने पर चिंता व्यक्त की है। सीजेआई सूर्यकांत ने विधिक सम्मेलन में अनेक राज्यों से आए अधिवक्ताओं एवं विधिक विशेषज्ञों के बीच कहा कि अवमानना के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। इस पर केंद्र एवं राज्य सरकार को चिंतन करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश के अनुसार राज्य सरकारों के समर्थन में फैसले नहीं आते तो वह हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई अवमानना याचिकाओं पर अप्रत्यक्ष में नाराजगी व्यक्त करते है। बिहार उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मप्र एवं छग में उच्च न्यायालयों में अनेक संगठनों द्वारा उनकी याचिका पर फैसला सरकार के विरुद्ध आता है तो राज्य सरकारें इसे लागू नहीं करती जबकि संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकारों का यह दायित्व है कि वह प्रजातंत्र के तीसरे खंभे न्यायापालिका जो सजग प्रहरी भी है के न्यायाधीशों द्वारा दिये गये मामलों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें। सीजेआई सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि वैसे भी उच्च न्यायालयों एवं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मामले करोड़ों की संख्या में है।

कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट खराब होने से फंसे बीजेपी नेता सहित कई लोग

रायपुर। राजधानी रायपुर में एक बार फिर लिफ्टकांड हो गया. रजबंधा मैदान स्थित निजी कॉम्प्लेक्स में मंगलवार को अचानक लिफ्ट खराब हो गई, जिसमें भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी समेत 7 लोग अंदर लगभग 15 मिनट तक फंसे रहे. मौके पर हड़कंप मच गया. किसी तरह सुरक्षा गार्ड ने दरवाजे खुलवाकर उन्हें बाहर निकाला. घटना का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कॉम्प्लेक्स प्रबंधन पर ठिकरा फोड़ा. भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि इस कॉम्प्लेक्स में पहले भी लिफ्ट खराब होने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं. कभी बुजुर्ग तो कभी महिलाएं यहां लिफ्ट में फंस जाती हैं. उन्होंने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने प्रशासन से नियमों के तहत कार्रवाई की मांग की है. जानकारी के मुताबिक, निजी कॉम्प्लेक्स में भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी और अन्य लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे. इस दौरान लिफ्ट अचानक बंद हो गया. सभी ने बार-बार अलार्म और फोन से मदद मांगने की कोशिश की, हालांकि तत्काल किसी प्रकार की तकनीकी सहायता नहीं मिल सकी. बाद में कॉम्प्लेक्स के सुरक्षा गार्ड और कर्मचारियों ने मशक्कत कर लिफ्ट का गेट खुलवाया. इसके बाद सभी सुरक्षित बाहर निकल गए।

शादी में गया परिवार, पीछे टूटा ताला; 24 मामलों वाला शातिर चोर गिरफ्तार

रायपुर। रिश्तेदार की शादी में गया परिवार जब घर लौटा तो ताले टूटे थे, पेटी खाली थी और घर का सामान गायब था, लेकिन गांधीनगर पुलिस ने कुछ ही दिनों में ऐसा शिकंजा कसा कि 24 मामलों में शामिल शातिर चोर आखिरकार पकड़ में आ गया। सरगुजा जिले के थाना गांधीनगर क्षेत्र में हाई स्कूल के पीछे स्थित मकान में हुई इस चोरी की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। प्रार्थी 14 मई 2026 को अपने घर में ताला लगाकर रिश्तेदारी में शादी समारोह में गया था। 17 मई को वापस लौटने पर उसने देखा कि मकान के मुख्य दरवाजे और पेटी का ताला टूटा हुआ है। घर में रखे एक सोने का लॉकेट, दो नग कान की बाली, 2000 रुपए नगद और चावल की बोरी चोरी हो चुकी थी। शिकायत मिलते ही थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 285/2026 के तहत धारा 331(4), 305ए बीएनएस में मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस टीम लगातार संदिग्धों की तलाश कर रही थी तभी मुखबिर से सूचना मिली कि बनारस रोड पेट्रोल पंप के पास एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर भन्जू वासुदेव को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने चोरी की पूरी वारदात कबूल कर ली और बताया कि चोरी का सामान खेत में छिपाकर रखा है।

चरित्र शक में पत्नी की हत्या चार मासूम अनाथ हुए आरोपी पति गिरफ्तार

रायपुर। चरित्र शंका ने एक हंसते-खेलते परिवार को पलभर में तबाह कर दिया, पति ने पत्नी को डंडे से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया और पीछे छूट गए चार मासूम बच्चे, जिनकी आंखों के सामने उनका पूरा संसार उजड़ गया। कोरिया जिले के थाना पटना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परसाभारी बुढार में 18 मई 2026 को हुई इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मामले में प्रार्थी जगमोहन पंडो पिता स्वर्गीय भंडारी पंडो निवासी ग्राम परसाभारी बुढार ने थाना पटना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी रंगसाय पंडो ने अपनी पत्नी सोनामती पंडो पर चरित्र शंका करते हुए डंडे से हमला कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी रंगसाय पंडो ग्राम परसाभारी बुढार थाना पटना जिला कोरिया का रहने वाला है।

आत्मनिर्भरता, पोषण और बदलाव की नई पहचान बनीं महिला स्व-सहायता समूह

पूरक पोषण आहार निर्माण का कार्य अब महिलाओं के हाथो

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और कुपोषण मुक्ति को एक साथ जोड़ते हुए राज्य सरकार ने एक ऐसी पहल शुरू की है, जिसने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आशा, आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिरता की नई रोशनी जगाई है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पूरक पोषण आहार (रेडी-टू-ईट) के निर्माण एवं वितरण का दायित्व महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपकर सरकार ने महिलाओं को केवल रोजगार ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें विकास की मुख्यधारा में सशक्त भागीदारी का अवसर भी प्रदान किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रारंभ की गई यह पहल राज्य में महिला सशक्तिकरण और पोषण सुरक्षा के समन्वित मॉडल के रूप में उभर रही है। पहले जहां पूरक पोषण आहार निर्माण का कार्य बाहरी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता था, वहीं अब यह जिम्मेदारी गांव की महिलाओं ने संभाल ली है, इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित हुआ है और महिलाओं की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रही है। राज्य सरकार ने प्रथम चरण में रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलें में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया है। इन छह जिलें के 42 महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी-टू-ईट पोषण आहार निर्माण एवं वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन समूहों के माध्यम से हजारों महिलाओं को रोजगार मिली है और वे अब संगठित रूप से उत्पादन, पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण का कार्य संभाल रही हैं। प्रदेश का पहला रेडी-टू-ईट उत्पादन रायगढ़ जिले में प्रारंभ हुआ, जिसने पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया। कोरबा जिले में 10, रायगढ़ में 10, सूरजपुर एवं बलौदाबाजार-भाटापारा में 7-7, बस्तर में 6 तथा दंतेवाड़ा में 2 महिला स्व-सहायता समूह इस कार्य से जुड़ी हुई हैं। इन समूहों के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों तक समय पर गुणवत्तापूर्ण पूरक पोषण आहार पहुंचाया जा रहा है। इस पहल का सबसे

महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे महिलाओं की भूमिका केवल श्रमिक तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे प्रबंधन और निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा भी बनी हैं। उत्पादन इकाइयों में कार्यरत महिलाओं को मशीन संचालन, गुणवत्ता परीक्षण, पैकेजिंग, भंडारण वितरण और लेखा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित इन इकाइयों ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। सूरजपुर जिले में संचालित रेडी-टू-ईट निर्माण संयंत्र इस बदलाव की सशक्त तस्वीर प्रस्तुत कर रही हैं। भैयाथान, प्रतापपुर और सूरजपुर विकासखंडों में संचालित संयंत्रों में महिलाएं पौष्टिक नमकीन दलिया और मीठा शक्ति आहार तैयार कर रही हैं। इन खाद्य पदार्थों में विटामिन 'ए', विटामिन 'डी', आयरन, कैल्शियम, जिंक और फोलिक एसिड जैसे आवश्यक पोषक तत्व शामिल हैं, जो बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इन संयंत्रों में कार्यरत महिलाएं अब केवल अपने परिवार की जिम्मेदारियां नहीं निभा रहीं, बल्कि जिले के पोषण अभियान में महत्वपूर्ण भागीदार बन चुकी हैं। सूरजपुर जिले में निर्माण के साथ-साथ वितरण की जिम्मेदारी भी महिला समूहों को सौंपी गई है, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं आजीविका से जुड़ सकी हैं। लगभग 430 महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों तक पोषण आहार पहुंचाने के कार्य में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने इस पहल को महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और बच्चों के बेहतर पोषण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उनका कहना है कि यह योजना महिलाओं को रोजगार देने के साथ-साथ राज्य के पोषण स्तर में सुधार लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दरअसल, यह पहल केवल पोषण आहार निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव की एक सशक्त कहानी भी है, जिन महिलाओं की पहचान कभी केवल घरेलू कार्यों तक सीमित थी, वे आज उत्पादन इकाइयों का संचालन कर रही हैं।

आमासिवनी में युवक का मर्डर लाइव वीडियो आया सामने.....

रायपुर/ संवाददाता

राजधानी रायपुर के आमासिवनी इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर हुई खूनी झड़प में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला आमासिवनी स्थित विधानसभा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, पैसे की लेनदेन को लेकर हुए विवाद के बाद तीन बदमाशों ने मिलकर युवक सुकृत खांडे की बेरहमी से हत्या कर दी, युवक की खून से साणे इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए राकेश गुप्ता उर्फपानी, देवदास उर्फहड्डी, विनोद उर्फविक्की और एक 16 वर्षीय नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक की पहचान सुकृत खांडे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुकृत खांडे का दिन के समय राकेश पांडे उर्फपानी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन रात होते-होते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पुरानी रंजिश और दिन में हुए विवाद को लेकर दोनों गुट आमने-सामने आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात में दोनों पक्षों के बीच पहले जमकर बहस हुई, जिसके बाद आरोपियों ने सुकृत खांडे पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में मातम छा गया और इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही विधानसभा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और आरोपियों की तलाश में दबिश दी।

भीषण गर्मी से बेहाल हाथी ने सूंड से खुद पर की पानी की बौछार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब वन्यजीवों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। बढ़ते तापमान और जंगलों में सूखते जलस्रोतों के बीच वन्यजीव पानी की तलाश में आबादी वाले इलाकों की ओर पहुंच रहे हैं। इसी बीच रायगढ़ और ओडिशा सीमा क्षेत्र से एक हाथी का दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक एक जंगली हाथी गांव के पास बने जलस्रोत तक पहुंचा, जहां उसने गर्मी से राहत पाने के लिए अपनी सूंड से बार-बार शरीर पर पानी की बौछार की। हाथी का यह अनोखा अंदाज वहां मौजूद ग्रामीणों को आकर्षित कर गया। लोगों ने इस पूरे दृश्य को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

संग्राहकों को हो रहा है सीधा ऑनलाइन भुगतान

अबूझमाड़ में महुआ प्रसंस्करण के लिए बनेगा जनजातीय सहकारी मॉडल.....

- आदिवासी समुदाय की अतिरिक्त आय हेतु लघु वनोपज संघ की बैठक में विचार-विमर्श

रायपुर/ संवाददाता

अबूझमाड़ क्षेत्र के विकास और वहां जनजातीय (आदिवासी) नेतृत्व में महुआ प्रसंस्करण के लिए एक प्रभावी सहकारी मॉडल विकसित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में समर्थन मूल्य पर तेंदूपत्ता संग्रहण तथा आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए वन धन योजना और ट्राईफेड के तहत महुआ प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की कार्ययोजना पर भी विमर्श किया गया। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहाँ मंत्रालय (महानदी भवन) में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी लघु वनोपज संघ की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि वन धन सहकारी समितियों द्वारा महुआ के फूलों से विभिन्न प्रकार के मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं। महुआ लड्डू और कुकीज, महुआ स्क्वैश (शरबत), महुआ का अचार और महुआ उत्पादों की प्रोसेसिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने हेतु स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया। बैठक में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य की भी समीक्षा की गई। इस दौरान संग्रहण से जुड़े व्यापार में सरकार को वित्तीय हानि से बचाने और संग्राहकों को अधिक से अधिक लाभांश पहुंचाने की रणनीतियों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा वर्तमान में संग्राहकों को पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था के तहत सीधे ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट.....

- तेज आंधी और हवाओं से बढ़ेगी मुश्किलें

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भीषण गर्मी और उमस के बीच अब प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और गरज-चमक का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी और विदर्भ क्षेत्र में सक्रिय चक्रवाती सिस्टम का असर प्रदेश के मौसम पर साफ दिखाई दे रहा है। इस बदलाव से तापमान में गिरावट और मौसम में नमी बढ़ने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान रायपुर, बस्तर, दुर्ग, महासमुंद और आसपास के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। राजधानी रायपुर में शनिवार को 62.8 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि बस्तर संभाग के कई इलाकों में भी जोरदार बारिश हुई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। दिनभर बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहावना बना रहा। ग्रामीण इलाकों में किसानों ने भी इस बारिश को राहत भरी बताया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बिलासपुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और बादलों की सक्रियता के कारण अगले कुछ दिनों तक तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा पश्चिम विदर्भ से मन्नार की खाड़ी तक एक द्रोणिका बनी हुई है, जो लगातार नमी को मध्य भारत और छत्तीसगढ़ की ओर खींच रही है।

छत्तीसगढ़ में जनजातीय गरिमा उत्सव अभियान शुरू, गांव-गांव पहुंचेंगी सरकारी योजनाएं

रायपुर। भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के निर्देशानुसार 'जनजातीय गरिमा उत्सव' के अंतर्गत 'जन भागीदारी सबसे दूर, सबसे पहले' थीम पर आधारित अभियान का प्रदेश स्तर पर शुभारंभ किया गया। यह अभियान मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, जनजातीय गरिमा उत्सव प्रदेश के जनजातीय बसाहटों के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में जनजातीय क्षेत्रों का विकास बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे मजबूत नींव पर ही मजबूत भवन तैयार होता है, उसी प्रकार विकसित भारत के निर्माण में जनजातीय गांवों का शत-प्रतिशत विकास आधारशिला का कार्य करेगा। मंत्री नेताम ने बताया कि पीएम जनमन योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, आदि कर्मयोगी अभियान और सर्वेसेतु ऐप में बेहतर प्रदर्शन के कारण छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बनाई है। उन्होंने अधिकारियों से अभियान के मूल उद्देश्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का आह्वान किया। आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और आयुक्त डी. राहुल वेकंट के नेतृत्व में अभियान की लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है।

विधानसभा को पेपरलेस करने के कार्यों में आएगी तेजी सचिव बंसल

- लोक निर्माण विभाग के सचिव ने विधानसभा भवन का किया निरीक्षण
- पर्याप्त पार्किंग के साथ सर्वसुविधायुक्त ड्राइवर-रूम बनाने के दिए निर्देश

रायपुर/ संवाददाता

लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने आज नवा रायपुर में निर्माणाधीन लोकभवन (राजभवन) के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे परिसर का भ्रमण कर ले-आउट और फ्लोर-प्लान जाना। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री बंसल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विधानसभा को 'पेपरलेस' बनाने के लिए तकनीकी कार्यों और व्यवस्थाओं में तेजी लाने लोक निर्माण विभाग और चिप्स को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता श्री टी.आर. कुंजाम, अधीक्षण अभियंता श्री डी.के. नेताम और कार्यपालन अभियंता श्री अभिनव श्रीवास्तव भी इस दौरान मौजूद थे। लोक निर्माण विभाग के सचिव ने 'लोकभवन' का निर्माण राज्यपाल की गरिमा के अनुरूप उत्कृष्टता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूरे परिसर के सौंदर्य, सूरज की रोशनी और पूर्ण उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने को कहा। उन्होंने भवन की सभी बारीकियों पर पुख्ता काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रमों के आयोजन के लिए यहां बन रहे सभा-भवनों और कार्यालयीन कक्षों की बैठक व्यवस्था पहले से ही निर्धारित कर उनके अनुरूप कार्यों को अंजाम देने को कहा। उन्होंने भवन के निर्माण कार्य में लगे अलग-अलग एजेंसियों से कार्य प्रगति की जानकारी लेकर यथाशीघ्र सभी कार्य पूर्ण कर इसे लोक निर्माण विभाग को हैंड-ओवर करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री बंसल ने नए विधानसभा भवन में प्रवेश द्वार, सदन, अधिकारी दीर्घा, लॉबी, डाइनिंग एरिया, मीडिया ब्रीफिंग एरिया, समिति कक्ष, मुख्यमंत्री कार्यालय, विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय, उप मुख्यमंत्रियों तथा मंत्रियों के कार्यालयों, ऑफिसर लाउंज और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों के कार्यालयों का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने सभी कार्यालयीन कक्षों में समुचित फर्नीचर और बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत ग्राम चंदौरा में आयोजित

जनसमस्या निवारण शिविर में 319 आवेदन प्राप्त हुए और 114 का मौके पर निराकरण किया गया

- जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना, शासन का उद्देश्य : प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल

रायपुर/ संवाददाता

सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जिले के प्रतापपुर जनपद पंचायत के ग्राम चंदौरा में आज जनसमस्या निवारण शिविर का भव्य आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सूरजपुर जिले के प्रभारी एवं प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री दयालदास बघेल ने की, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री रामसेवक पैकरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं, शिकायतें एवं मांगें प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कीं। शिविर में कुल 319 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 114 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया तथा शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए। ग्रामवासियों को सम्बोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन का संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि अधिक से अधिक लोग सुशासन तिहार अंतर्गत आयोजित शिविरों का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शासन ने पारदर्शिता के साथ धान खरीदी की है तथा किसानों को राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया है। राज्य के जरूरतमंद एवं कमजोर वर्गों को नियमित रूप से खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु उन्होंने किसानों से मिट्टी परीक्षण कराने एवं शासन की योजनाओं के तहत खाद-बीज प्राप्त करने की अपील की।

संपादकीय

आंधी-तूफान से आखिर हर साल क्यों बेबस दिखते हैं लोग?

पिछले कुछ वर्षों से हर बार यह देखा जाता है कि एक ओर तूफान में पेड़ या घर गिरने जैसी घटनाओं की वजह से कई लोग मारे जाते हैं, तो दूसरी ओर घर से लेकर फसलों तक को व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान, बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जैसे हालात पैदा हुए, उसने एक बार फिर यही दर्शाया कि मौसम की मार से बचाव के लिए एहतियात बरतने से लेकर सटीक पूर्वानुमान को लेकर तकनीकी स्तर पर अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। राज्य के कई इलाकों में बुधवार की शाम को तेज आंधी-तूफान, बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि एक तरह से कहर बरपा रही थी और आम लोग उसके सामने लाचार थे।कई जगहों पर तेज हवाओं ने भारी तबाही मचाई। कितनी ही जगहों पर भारी पेड़ उखड़कर वाहनों पर गिर गए और सड़कों के किनारे लगे बोर्ड उड़कर तेज रफ्तार से जमीन पर गिरे। करीब चौबीस घंटों के दौरान करीब सौ लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। कई जिलों में दो हजार से ज्यादा गांवों में बिजली गुल हो गई। कुदरत के इस कहर के बाद मौसम विभाग ने राज्य के अड़तीस जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की आशंका के मद्देनजर पीली चेतावनी जारी की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूर्वानुमानों के बावजूद कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, जिनमें तूफान या बिजली गिरने की घटनाएं आम लोगों पर कहर बनकर टूटती हैं।जाहिर है, मौसम की अपनी गति होती है और प्रकृति में उथल-पुथल के नतीजे में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि अमूमन हर वर्ष अचानक मौसम का रुख बिगड़ने की आशंका के बावजूद आम लोग इससे बचाव के लिए एहतियात नहीं बरत पाते। इसका खमियाजा यह सामने आता है कि जिन हालात में कुछ लोगों की जान बच सकती थी, उसमें नाहक ही कई लोगों की जान चली जाती है।राज्य में मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती ढांचे और दक्षिण राजस्थान से आ रही हवाओं के प्रभाव से वहां कई जगहों पर अस्सी से सौ किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। नतीजतन, बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ। कई जगहों पर न केवल घरों की छत उड़ गई, बल्कि लोगों के लिए पांव टिकाना भी मुश्किल था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे मौसम में बचाव को लेकर जरूरी प्रशिक्षण के अभाव का नुकसान आम लोगों को किस स्तर पर उठाना पड़ता है।संभव है कि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के साथ-साथ मौसम साफ होने लगे और उसके बाद तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो, लेकिन इसके साथ यह भी सच्चाई है कि साल के इन महीनों में कई बार तेज रफ्तार से चलने वाला तूफान और ओलावृष्टि कई स्तर पर आम लोगों के लिए व्यापक क्षति और खतरे का वाहक बनते हैं।पिछले कुछ वर्षों से हर बार यह देखा जाता है कि एक ओर तूफान में पेड़ या घर गिरने जैसी घटनाओं की वजह से कई लोग मारे जाते हैं, तो दूसरी ओर घर से लेकर फसलों तक को व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचता है।

सत्ता संभालते ही हिंदुत्व मॉडल के जरिये बंगाल में बड़े बदलाव कर रहें सुवेंदु अधिकारी

(नीरज कुमार दुबे)

नई सरकार के शुरुआती फैसलों में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर सख्ती प्रमुख रही। सरकार ने स्पष्ट किया कि सड़कों और सार्वजनिक मार्गों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी तथा धार्मिक गतिविधियां निर्धारित परिसरों तक सीमित रहेंगी।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सत्ता की कमान संभालते ही चुनावी वादों पर अमल की दिशा में कदम बढ़ाने तो शुरू कर ही दिये हैं साथ ही राज्य की राजनीति और प्रशासन में तेज बदलावों का दौर भी शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिन्हें राज्य की दिशा बदलने वाला माना जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को उनके गढ़ में पराजित कर सत्ता तक पहुंचे सुवेंदु अधिकारी ने शपथ लेने के केवल 48 घंटे के भीतर लगभग डेढ़ दर्जन बड़े निर्णयों की घोषणा कर यह संकेत दे दिया कि नई सरकार प्रशासनिक, राजनीतिक और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर व्यापक बदलाव चाहती है।

नई सरकार के शुरुआती फैसलों में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर सख्ती प्रमुख रही। सरकार ने स्पष्ट किया कि सड़कों और सार्वजनिक मार्गों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी तथा धार्मिक गतिविधियां निर्धारित परिसरों तक सीमित रहेंगी। कोलकाता के रेड रोड क्षेत्र में सार्वजनिक नमाज पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी नियंत्रण लगाया गया है। सरकार ने पत्थरबाजी की घटनाओं पर भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

साथ ही सुवेंदु अधिकारी सरकार ने वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव और वर्ष 2023 के पंचायत चुनावों के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों को फिर से खोलने का आदेश दिया है। इन मामलों को पिछली सरकार के दौरान बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित और बंद मामलों की दोबारा जांच कराने का निर्देश दिया। सरकार का कहना है कि चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाना उसकी प्राथमिकता है।

इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के मामलों को भी दोबारा जांच के दायरे में लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पंद्रह वर्षों में मारे गए तीन सौ इक्कीस भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवार यदि चाहें तो सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी। यह फैसला राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर भाजपा के लंबे अभियान का हिस्सा माना जा रहा है।

इसके अलावा, नई सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई करने और पुलिस को बिना राजनीतिक दबाव के काम करने की खुली छूट देने की घोषणा की है। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और किसी की राजनीतिक पहचान को महत्व न दिया जाए। सरकार ने दावा किया है कि कानून व्यवस्था को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त किया जाएगा।

साथ ही सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ और पशु तस्करी के मुद्दे पर भी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य में अवैध पशु बाजारों को बंद करने और अवैध परिवहन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर चौबीस परगना जिलों में चल रहे अवैध पशु बाजारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इसके साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को पैंतालीस दिनों के भीतर भूमि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे अवैध घुसपैठ और जनसंख्या संतुलन में हो रहे बदलावों पर रोक लगेगी।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने राज्य में पशु वध को लेकर भी सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार अब किसी भी पशु के वध से पहले उसकी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र नगर निकाय प्रमुख और सरकारी पशु चिकित्सक की संयुक्त सहमति से जारी किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और केवल निर्धारित बूचड़खानों में ही इसकी अनुमति होगी। नियमों के उल्लंघन पर छह महीने तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। नई सरकार के इस कदम को कानून व्यवस्था, सार्वजनिक स्वच्छता और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

साथ ही राज्य में लंबे समय से चर्चा में रहे सिंडिकेट राज और अवैध खनन पर भी सरकार ने कार्रवाई का संकेत दिया है। जिला और प्रखंड स्तर पर सक्रिय कथित सिंडिकेट नेटवर्क को समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि पिछली व्यवस्था में निर्माण सामग्री और कई क्षेत्रों में प्रभावशाली समूहों का नियंत्रण

था, जिसे खत्म करना आवश्यक है।

सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव करते हुए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की सुरक्षा हटाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस शासनकाल में विभिन्न बोर्डों, सार्वजनिक उपक्रमों और गैर वैधानिक संस्थाओं में नियुक्त अध्यक्षों और सदस्यों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश दिए गए हैं। साठ वर्ष से अधिक आयु वाले अधिकारियों को सेवा विस्तार देने पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। नई सरकार ने केंद्र की कई योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्री योजना, विश्वकर्मा योजना और उज्ज्वला योजना को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को केंद्र सरकार के साथ आवश्यक समझौते तेजी से पूरा करने को कहा है। साथ ही राज्य की नई भाजपा सरकार ने शिक्षा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़े मोर्चे पर भी बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम् गाना अनिवार्य कर दिया है। आदेश के अनुसार कक्षाएं शुरू होने से पहले विद्यार्थियों को वंदे मातरम् के छहों पद गाने होंगे। सरकार का कहना है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह गीत देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वंदे मातरम् को जन गण मन के समान दर्जा दिए जाने के बाद इस निर्णय को और अधिक महत्व दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसे राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

इसके अलावा, कानूनी ढांचे में बदलाव करते हुए भारतीय न्याय संहिता को राज्य में लागू करने की घोषणा भी की गई है। यह नया आपराधिक कानून पुराने भारतीय दंड संहिता का स्थान ले चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसका कार्यान्वयन लंबित था। नई सरकार ने इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है।

सरकारी नौकरियों के इच्छुक युवाओं को राहत देते हुए आयु सीमा चालीस से बढ़ाकर पैंतालीस वर्ष कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे लंबे समय से अवसरों से वंचित युवाओं को लाभ मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।

जनगणना प्रक्रिया को भी नई सरकार ने फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के निर्देशों के बावजूद यह प्रक्रिया लंबे समय से लंबित थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब बिना किसी राजनीतिक अहंकार के केंद्र के निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगी।

इसके अलावा, प्रशासनिक ढांचे में सुधार की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस अधिकारियों को केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजने का फैसला किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय स्तर के मानकों से जोड़ना है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के आठ अधिकारियों ने नई दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया। शहरी विकास विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इसे पश्चिम बंगाल की नौकरशाही में बड़े प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत माना जा रहा है। बहरहाल, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुवेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही हिंदुत्व आधारित राजनीति को जमीन पर उतारने की दिशा में तेज कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पर सख्ती, वंदे मातरम् को अनिवार्य करना, सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई जैसे फैसलों को इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

वैश्विक संकटों के दौर में परिवार ही रिश्तों की अंतिम शरणस्थली

(ललित गर्ग)

आज दुनिया का सबसे बड़ा संकट आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और नैतिक संकट है। बाजार की चकाचौंध ने आदमी को उपभोक्ता तो बना दिया, लेकिन संवेदनशील इंसान नहीं बना सकी। संबंधों में स्वार्थ का प्रवेश हुआ है। विश्वास की जगह संदेह ने ले ली है। आदमी मशीनों से जुड़ रहा है, लेकिन अपनों से कटता जा रहा है।

हर वर्ष 15 मई को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस एक मानवीय रिश्तों का उत्सव ही नहीं, बल्कि मानव सभ्यता को उसकी जड़ों की याद दिलाने का अवसर है। यह दिन हमें बताता है कि दुनिया चाहे कितनी भी आधुनिक, तकनीकी और आर्थिक रूप से विकसित क्यों न हो जाए, मनुष्य की सबसे पहली जरूरत आज भी परिवार ही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यह दिवस इस वर्ष विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी दुनिया बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, युद्ध, हिंसा, मानसिक तनाव, अकेलेपन और टूटते मानवीय विश्वासों के संकट से गुजर रही है। ऐसे कठिन समय में परिवार केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि मनुष्य के अस्तित्व, सुरक्षा, संस्कार और संवेदनाओं की सबसे मजबूत छत बनकर सामने आता है।

आज दुनिया का सबसे बड़ा संकट आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और नैतिक संकट है। बाजार की चकाचौंध ने आदमी को उपभोक्ता तो बना दिया, लेकिन संवेदनशील इंसान नहीं बना सकी। संबंधों में स्वार्थ का प्रवेश हुआ है। विश्वास की जगह संदेह ने ले ली है। आदमी मशीनों से जुड़ रहा है, लेकिन अपनों से कटता जा रहा है। युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जा रहे, वे परिवारों के भीतर भी दिखाई देने लगे हैंकृपति-पत्नी के बीच, पीढ़ियों के बीच, भाई-भाई के बीच। संवाद टूट रहे हैं, सहनशीलता घट रही है और 'मैं' का अहंकार 'हम' की भावना को निगलता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में परिवार की भूमिका पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। परिवार केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं है, वह जीवन-मूल्यों का विद्यालय है। वहीं मनुष्य पहली बार प्रेम सीखता है, त्याग सीखता है, सहयोग, अनुशासन, धैर्य और सह-अस्तित्व की भावना सीखता है। यदि परिवार स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र और विश्व भी संतुलित रहेंगे। इसलिए आज आवश्यकता केवल परिवार बचाने की नहीं, बल्कि परिवारों को मूल्यनिष्ठ बनाने की है। आज जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, जीवन की आवश्यकताएं महंगी होती जा रही हैं और बेरोजगारी युवाओं के सपनों को तोड़ रही है, तब संयुक्त परिवार की अवधारणा फिर प्रासंगिक बनती दिखाई दे रही है। संयुक्त परिवार केवल आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा का भी आधार है। वहां संसाधनों का साझा उपयोग होता है, जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं और संकट अकेले व्यक्ति पर नहीं टूटता। अकेलेपन से उपजी अवसाद की समस्याएं संयुक्त परिवारों में अपेक्षाकृत कम दिखाई देती हैं क्योंकि वहां संवाद और अपनापन जीवित रहता है। वास्तव में आधुनिक सभ्यता ने स्वतंत्रता तो दी, लेकिन उस स्वतंत्रता ने कई बार व्यक्ति को संबंध-विहीन भी बना दिया। महानगरों के छोटे-छोटे फ्लैटों में रहने वाले हजारों लोग आर्थिक रूप से संपन्न होकर भी भीतर से बेहद अकेले हैं। वृद्ध माता-पिता उपेक्षा के शिकार हैं, बच्चे संस्कारों से दूर हो रहे हैं और पति-पत्नी के बीच संबंधों की ऊष्मा कम होती जा रही है। यही कारण है कि मानसिक रोग, तनाव, असुरक्षा और आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह केवल व्यक्तिगत विफलता नहीं, परिवार संस्था के कमजोर पड़ने का संकेत है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि परिवार को केवल उपभोग और सुविधा का केंद्र न बनाकर उसे अहिंसा की प्रयोगशाला बनाया जाए। अहिंसा का अर्थ केवल किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाना नहीं है। कठोर शब्दों से बचना, अपमान न करना, एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, क्रोध पर संयम रखना, संवाद बनाए रखना और क्षमा का अभ्यास करना भी अहिंसा है। यदि परिवार के भीतर हिंसक भाषा, कटुता, अपमान और असहिष्णुता होगी तो समाज में शांति की कल्पना कैसे की जा सकती है? परिवार वह पहला स्थान होना चाहिए जहां बच्चा सहिष्णुता और करुणा का पाठ सीखे। जहां उसे यह सिखाया जाए कि जीवन प्रतियोगिता नहीं, सह-अस्तित्व है। जहां बुजुर्ग बोझ नहीं, अनुभवों की धरोहर माने जाएं। जहां स्त्री को सम्मान मिले, बच्चों को संस्कार मिले और युवाओं को विश्वास मिले। आज दुनिया में बढ़ती हिंसा का एक बड़ा कारण यह भी है कि परिवारों में संवाद और संवेदना कमजोर हो रही है। बच्चे मोबाइल से बातें कर रहे हैं, लेकिन माता-पिता से नहीं। परिवार साथ रहते हुए भी भीतर से बिखर रहा है। जलवायु परिवर्तन, युद्ध और आर्थिक अस्थिरता ने पूरी दुनिया को असुरक्षित बना दिया है।

ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों के 'दिल्ली-विमर्श' के निहितार्थ

(कमलेश पांडे)

देखा जाए तो नई दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। दो दिनों का यह 18वां शिखर सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है, जब दुनिया कई मोर्चे पर अस्थिरता से गुजर रही है। ब्रिक्स के सदस्य देश - ईरान और यूएई सीधे तौर पर इस हलचल में शामिल है। ऐसे में यह जुटान पूरी दुनिया के लिए अहम हो जाती है।

ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय दिल्ली बैठक ने दुनिया को कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक संदेश दिए हैं, जिनके कूटनीतिक निहितार्थ को समझने की जरूरत है। अन्यथा शेष दुनिया को अमेरिकी-यूरोपीय दादागिरी (नाटो सैन्य गठबंधन) के दुनियावी दावपेंचों से निजात मिलनी मुश्किल है। लिहाजा, इस बैठक में मुख्य रूप से वैश्विक शक्ति-संतुलन, अमेरिकी प्रतिबंध नीति, पश्चिम एशिया संकट, वैश्विक व्यापार व्यवस्था और 'ग्लोबल साउथ' की भूमिका पर जोर दिखाई दिया।

देखा जाए तो नई दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। दो दिनों का यह 18वां शिखर सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है, जब दुनिया कई मोर्चे पर अस्थिरता से गुजर रही है। ब्रिक्स के सदस्य देश - ईरान और यूएई सीधे तौर पर इस हलचल में शामिल है। ऐसे में यह जुटान पूरी दुनिया के लिए अहम हो जाती है। इस अहम बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची जैसे नेताओं के दूरदर्शिता भरे बयान विशेष चर्चा में रहे। जिसके दुनियावी मायने बेहद अहम हैं।

जिस तरह से कूटनीतिक सम्मेलन के पहले ही दिन जयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ लगाए जाने वाले एकतरफा प्रतिबंधों का जिक्र किया, जो सबसे ज्यादा विकासशील देशों को नुकसान पहुंचाते हैं। स्वाभाविक तौर पर उनका इशारा अमेरिका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं, ईरान मामले में भी गतिरोध की वजह बहुत हद तक वाशिंगटन की अव्यवहारिक मांगें है। ब्रिक्स के बड़े मंच से उठी आवाज का असर ज्यादा होगा।

विदेश मंत्री एस जयशंकर का उद्घाटन भाषण मौजूदा चुनौतियों का सही खाका खींचता है। पश्चिम एशिया पर मंडराता युद्ध का खतरा, ऊर्जा संकट, सप्लाई चेन में रुकावट और जलवायु परिवर्तन ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को मंदी में फंसने का डर सता रहा है। ऐसे में जैसा कि विदेश मंत्री ने कहा, विकासशील देशों ने ब्रिक्स से यह उम्मीद लगाई है कि यह मंच स्थिरता कायम करने में सकारात्मक भूमिका अदा करेगा। इसके कतिपय निहितार्थ इस प्रकार हैं-

पहला, एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती- बैठक का सबसे बड़ा संदेश यह था कि दुनिया अब केवल अमेरिका-केन्द्रित व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना चाहती। ब्रिक्स देशों ने मल्टीपोलर वर्ल्ड के दृष्टिगत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। इसका अर्थ है कि वैश्विक निर्णयों में पश्चिमी देशों के साथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की शक्तियों की भी बराबर भूमिका हो।

दूसरा, अमेरिकी प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव का विरोध- भारत, रूस, चीन और ईरान सहित कई देशों ने एकतरफा प्रतिबंधों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और संप्रभुता के खिलाफ बताया। विशेष रूप से एस जयशंकर ने कहा कि प्रतिबंध और दबाव कूटनीति का विकल्प नहीं हो सकते। यह संदेश सीधे तौर पर अमेरिका की प्रतिबंध नीति की आलोचना माना गया।

तीसरा, डॉलर प्रभुत्व कम करने का संकेत- बैठक में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों पर भी चर्चा हुई। यह संदेश था कि ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं ताकि अमेरिकी आर्थिक दबाव का असर घटाया जा सके।

चतुर्थ, पश्चिम एशिया संकट पर चिंता- ईरान-इज़राइल तनाव और समुद्री मार्गों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा रहा। ब्रिक्स देशों ने रेड सी और होर्मुज़ जलडमरूमध्य जैसे मार्गों की सुरक्षा पर जोर दिया। दुनिया को यह संदेश दिया गया कि क्षेत्रीय युद्ध अब वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि इस मंच के सामने भी चुनौती है। ईरान और यूएई के आपसी रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। जबकि चीन ने अपने विदेश मंत्री को नहीं भेजा है।

एक बात और, जब सम्मेलन की शुरुआत हुई, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग तब ट्रंप की मेजबानी में व्यस्त थे। ब्रिक्स के सबसे बड़े विरोधी ट्रंप है। उन्हें लगता है कि यह मंच अमेरिकी हितों के खिलाफ खड़ा किया गया है। मेजबान होने के नाते यह भारत की जिम्मेदारी है कि यहां से निकला संदेश किसी के विरोध में नहीं, साझा हित में हो। भारत के पास सभी सदस्यों को करीब लाने और मौजूदा संकट का समाधान पेश करने का मौका है।

पांचवां, ग्लोबल साउथ की राजनीतिक आवाज- बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स स्वयं को केवल आर्थिक समूह नहीं, बल्कि विकासशील देशों की सामूहिक राजनीतिक आवाज के रूप में स्थापित करना चाहता है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों की समस्याओं- जैसे खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा संकट और कर्ज-को वैश्विक एजेंडा में प्रमुखता देने की बात कही गई। छठा, संयुक्त राष्ट्र सुधार की मांग- भारत और ब्राजील ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता दोहराई। यह संदेश था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी संस्थाओं में अब नई वैश्विक वास्तविकताओं के अनुसार बदलाव होना चाहिए। सातवां, ब्रिक्स के भीतर मतभेद भी सामने आए- हालांकि बैठक में एकजुटता दिखाई गई, लेकिन यह भी स्पष्ट हुआ कि सभी सदस्य अमेरिका-विरोधी नीति पर पूरी तरह एकमत नहीं हैं। भारत और ब्राजील जैसे देश पश्चिम के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना चाहते हैं, जबकि रूस और ईरान अधिक आक्रामक रुख चाहते हैं। इससे यह संकेत मिला कि ब्रिक्स अभी पूर्ण राजनीतिक गठबंधन नहीं, बल्कि साझा हितों वाला मंच है। समग्र रूप से कहा जाए तो, इस बैठक का वैश्विक संदेश यह था कि उभरती शक्तियाँ अब विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में अधिक स्वतंत्र, संतुलित और पश्चिम से अलग भूमिका चाहती हैं। ब्रिक्स ने यह दिखाने की कोशिश की कि ग्लोबल साउथ अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन का सक्रिय खिलाड़ी बनना चाहता है। चूंकि ब्रिक्स अब केवल उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह नहीं रहा, इसकी भूमिका आज कहीं ज्यादा व्यापक हो चुकी है। वास्तव में यह वैश्विक संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत का रोल इसमें सबसे अहम हो जाता है। उसने पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते बनाए हुए हैं, जबकि रूस, ईरान और चीन के साथ भी बैलेंस रखा है। उसने हमेशा संवाद से समाधान की बात की है। यह रवैया उसे भरोसेमंद साथी बनाता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक है)। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

नगर पालिका परिषद किरंदुल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 को लेकर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न

किरंदुल। नगरपालिका परिषद किरंदुल के कार्यालय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष रूबी शैलेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पार्षदगण, व्यापारी, दुकानदार, होटल संचालक एवं नगर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी शशि भूषण महापात्र ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 लागू किया गया है। इसके तहत नगर क्षेत्र में निकलने वाले सूखे एवं गीले कचरे का पृथक्करण, सुरक्षित परिवहन एवं वैज्ञानिक निपटान अनिवार्य किया गया है। नागरिकों से अपील की गई कि वे अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों में अलग-अलग डस्टबिन का उपयोग करें तथा स्वच्छता बनाए रखने में नगर पालिका का सहयोग करें। साथ ही बताया गया कि कचरा प्रबंधन के लिए चार प्रकार के डस्टबिन का उपयोग किया जाएगा, जिसमें गीला कचरा, सूखा कचरा, घरेलू हानिकारक कचरा एवं सैनिटरी वेस्ट को अलग-अलग एकत्रित किया जाएगा। बैठक में होटल संचालकों, मेडिकल स्टोर, किराना दुकानों, मैरिज हॉल एवं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को कचरा प्रबंधन संबंधी नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। उप अभियंता संजय मार्कण्डेय ने बताया कि सभी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में कचरा संग्रहण एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना एवं कार्रवाई की जाएगी।नगर पालिका परिषद किरंदुल द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन शिकायत एवं सुझाव प्रणाली शुरू किए जाने की जानकारी भी दी गई।अधिकारियों ने बताया कि स्वच्छता, कचरा उठाव, नाली सफाई एवं अन्य समस्याओं के समाधान हेतु नागरिक हेल्पलाइन नंबर एवं व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकेंगे।बैठक में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक कप, प्लेट, चम्मच, स्ट्रॉ एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्री के उपयोग एवं बिक्री पर कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों ने भी नगर को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। बैठक के अंत में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों एवं नागरिकों को नगर को स्वच्छ, सुंदर एवं प्लास्टिक मुक्त बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। सभी ने यह संकल्प लिया कि वे अपने घर, दुकान एवं प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखेंगे, कचरे का पृथक्करण करेंगे तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। साथ ही लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया गया।

इक्के नंबर सब्बो बर डॉल्फिन-112 सेवा शुरू अब एक कॉल पर मिलेगी पुलिस सहायता

कोंडागांव। कोंडागांव जिले में आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए डायल-112 सेवा और मोबाइल फोरेंसिक वैन का शुभारंभ किया गया। सिटी कोतवाली परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। इस अवसर पर बस्तर सांसद महेश कश्यप, कोण्डागांव विधायक लता उसेंडी, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना तथा पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा मौजूद रहे। एक्के नंबर सब्बो बर थीम पर शुरू की गई इस सेवा के तहत अब जिले के लोग 112 नंबर डायल कर पुलिस सहायता, महिला सुरक्षा, आगजनी और अन्य आपात स्थितियों में तत्काल मदद प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा कॉल के साथ-साथ व्हाट्सऐप और संदेश माध्यम से भी उपलब्ध रहेगी। जिले को कुल छह डायल-112 वाहन मिले हैं। इनमें तीन वाहन जिला मुख्यालय में तैनात रहेंगे, जबकि अन्य वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देंगे। इन वाहनों को डॉल्फिन नाम दिया गया है, जो त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया का प्रतीक माना जा रहा है। इसके साथ ही मोबाइल फोरेंसिक वैन की भी शुरुआत की गई है। यह चलित प्रयोगशाला की तरह कार्य करेगी, जिससे घटनास्थल पर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र किए जा सकेंगे। पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा ने बताया कि जिले में आधुनिक और कागज रहित पुलिस व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है, जिससे अपराधों की जांच और आपात सहायता व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी।

दो जिलों की संयुक्त टीम की तत्परता से रोका गया बाल विवाह

कांकेर। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए विकासखंड भानुप्रतापपुर के ग्राम पंचायत डोंगरकट्टा व्यापारीपारा में होने वाले बाल विवाह को समय रहते रोका गया। नाबालिग बालिका का विवाह 19 मई 2026 से महलिया (सगाई) की रस्म के साथ जिला बालोद के ग्राम तुमड़ीसुर के युवक के साथ शुरू होने वाला था। बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी की संयुक्त टीम जिसमें परियोजना अधिकारी भानुप्रतापपुर, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के परामर्शदाता एवं केसवर्कर तथा भानुप्रतापपुर पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे, द्वारा मौके पर पहुंचकर विवाह शुरू होने के कार्यक्रम को रोकने की कार्यवाही की गई। इस दौरान बालिका के आयु संबंधी दस्तावेज जैसे दसवीं की अंकसूची, आधार कार्ड आदि की जांच की गई। जांच में बालिका की आयु 17 वर्ष 7 माह तथा युवक की आयु 19 वर्ष पाई गई, जो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। जांच एवं सत्यापन उपरांत टीम ने बालिका के परिजनों, ग्रामवासियों एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही टीम की समझाइश पर परिजनों ने विवाह रोकने लिखित सहमति प्रदान की, जिसके बाद बाल विवाह को रोका गया। इसी प्रकार बालोद जिले की ग्राम पंचायत तुमड़ीसुर में भी नाबालिग युवक का विवाह किए जाने के संबंध में जानकारी मिलने पर संयुक्त टीम द्वारा तत्काल वर पक्ष के घर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की गई तथा वहां बाल विवाह रुकवाया गया। विभाग ने आमजन से अपील की है कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति की सूचना तत्काल संबंधित विभाग अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दें, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। कार्यवाही के दौरान जिला बाल संरक्षण अधिकारी, परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के परामर्शदाता और पुलिस विभाग की टीम शामिल थी।

बस्तर की पारंपरिक कला को राष्ट्रीय सम्मान विधायक लता उसेंडी ने गृह मंत्री को भेंट की भगवान गणेश की विशेष शिल्पकृति

कृति की अवधारणा एवं कलात्मक दृष्टि प्रसिद्ध मूर्तिकार सुशील सखूजा द्वारा विकसित की गई

कोण्डागांव। बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक शिल्पकला को राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोण्डागांव विधायक लता उसेंडी ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह को भगवान गणेश की विशेष शिल्पकृति भेंट कर बस्तर की कला का गौरव बढ़ाया। यह अद्वितीय शिल्पकृति बस्तर की पारंपरिक कला, आध्यात्मिक भावनाओं और स्थानीय शिल्प कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस कृति की अवधारणा एवं कलात्मक दृष्टि प्रसिद्ध मूर्तिकार सुशील सखूजा द्वारा विकसित की गई, जबकि इसे मूर्त रूप देने में आर्टिजन मदन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दोनों के समन्वित प्रयास से तैयार यह शिल्पकृति पारंपरिक बस्तर कला और आधुनिक रचनात्मकता का सुंदर संगम प्रस्तुत करती है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह शिल्पकृति केवल एक कलात्मक प्रस्तुति नहीं, बल्कि बस्तर की लोक परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान और शिल्प कौशल का प्रतीक है। राष्ट्रीय नेतृत्व को इस प्रकार की कृति भेंट किए जाने से स्थानीय कलाकारों को नई पहचान और प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस अवसर को बस्तर के शिल्पकार समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। इससे न केवल पारंपरिक कला को व्यापक मंच मिलेगा, बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी भेंट कर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, किरण सिंह देव, वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद भोजराज नाग, महेश कश्यप, विधायक नीलकंठ टेकाम, आशाराम नेताम, चौतराम अटामी, कमलचंद भंजदेव, सेवकराम नेताम, संजय पांडे, बैदूराम कश्यप सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार एवं जल जीवन मिशन के मिशन संचालक कमल किशोर सोन का कोंडागांव जिला भ्रमण

कोण्डागांव। कोंडागांव जिले के भ्रमण के दौरान अतिरिक्त सचिव भारत सरकार एवं जल जीवन मिशन के मिशन संचालक कमल किशोर सोन और एरिया अधिकारी उमेश भारद्वाज द्वारा विकासखंड फरसगांव के ग्राम जुगानी कलार में जल जीवन मिशन अंतर्गत क्रियान्वित एकल ग्राम पेयजल योजना का निरीक्षण किया गया। कार्यपालन अभियंता वीरेंद्र पांडे ने बताया कि ग्राम जुगानी कलार में जल जीवन मिशन अंतर्गत 215.03 लाख रुपए लागत की योजना स्वीकृत है तथा 65 किलोमीटर क्षमता की 01 आर.सी.सी. ऊँची पानी टंकी एवं 1 सौर टंकी है टंकियों के माध्यम से 409 घरों में जल प्रदाय किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत जुगानीकलार की सरपंच संगीता नेताम ने बताया कि योजना प्रारंभ होने के बाद अब ग्रामीणों को हैंडपंप पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, बल्कि घर-घर स्वच्छ पानी की आपूर्ति हो रही है। इससे ग्रामीणों को काफी राहत मिली है। निरीक्षण के दौरान योजना के संचालन, जल वितरण प्रणाली तथा पानी की गुणवत्ता जांच प्रक्रिया का अवलोकन किया गया। वर्षा ऋतु के पूर्व एवं पश्चात अधिक से अधिक जल परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त वर्ष में दो बार जल टंकियों की सफाई करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही जल स्रोतों की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु जल संरक्षण एवं भू-जल संवर्धन पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही प्रत्येक गांव के एक व्यक्ति को प्रशिक्षित कर मिशन के कार्यों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा नियमित अंतराल में पानी की टंकियों की सफाई कर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत परिवारों हेतु निर्मित शौचालयों के उपयोग के संबंध में ग्राम वासियों से जानकारी प्राप्त की गई तथा घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के उचित निपटान हेतु ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव को आवश्यक समझाइश दी गई।

ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में दवा कारोबारियों की हड़ताल

किरंदुल। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में दवा कारोबारियों ने राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है।इस हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ सहित दंतेवाड़ा जिले में भी देखने को मिल रहा है, जहां से ही निजी मेडिकल स्टोर बंद रहे।प्रदेशभर के दवा विक्रेता और मेडिकल संचालक ऑनलाइन दवा बिक्री व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। दवा कारोबारियों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से मेडिकल व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। साथ ही बिना उचित निगरानी के दवाइयों की बिक्री से मरीजों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। उनका कहना है कि दवाइयां विशेषज्ञ सलाह और निर्धारित नियमों के तहत ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मेडिकल स्टोर संचालक कहते हैं कि ऑनलाइन के दौर में नशे का कारोबार भी चल रहा है। बगैर चिकित्सक के पर्ची के प्रतिबंधित दवाएं भी ऑनलाइन मिलने की सूचनाएं मिलती है। बेहद आसानी से इन दवाओं की व्यवस्था होने से भावी पीढ़ी आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे में पूर्णरूप से ऑनलाइन दवा पर रोक लगना चाहिए। हड़ताल के चलते दंतेवाड़ा सहित प्रदेश के मरीजों को निजी दवा दुकानों से दवाइयां नहीं मिल सकेंगी। हालांकि अस्पताल परिसरों में संचालित मेडिकल स्टोर और सरकारी दवा केंद्र खुले रहेंगे, जहां से मरीज आवश्यक दवाइयां प्राप्त कर सकेंगे। हड़ताल के कारण अचानक दवा की जरूरत वाले लोगों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों एवं महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस का आक्रोश प्रदर्शन

नारायणपुर। पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों, ईंधन संकट एवं बेलगाम महंगाई के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जनआक्रोश प्रदर्शन करते हुए शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों में पहुंचकर विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना तथा केंद्र एवं राज्य की बीजेपी सरकार की विफल नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। जिला कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आम जनता पेट्रोल-डीजल की कमी और बढ़ती महंगाई से परेशान होकर रात-दिन सड़कों पर लंबी कतारों में खड़े रहने को मजबूर है। किसानों, मजदूरों, व्यापारियों एवं आम उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार और उसके मंत्री जनता की समस्याओं से बेखबर होकर केवल दिखावे और प्रचार में व्यस्त है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक ओर जनता महंगाई, बेरोजगारी और ईंधन संकट से जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार समस्याओं के समाधान के बजाय अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास कर रही है। जिला कांग्रेस ने मांग की कि पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, बढ़ती कीमतों पर तत्काल नियंत्रण लगाया जाए तथा आम जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि जनता अब बीजेपी सरकार की जनविरोधी नीतियों को समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। धरना प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष राजेश दीवान, प्रदेश महामंत्री रजनू नेताम प्रदेश सचिव देवनाथ उसेंडी शहर कांग्रेस अध्यक्ष रघु मानिकपुरी जिला कोषध्यक्ष वी पी शुक्ला जिला महमंत्री संगठन संजय राय महामंत्री प्रशासनिक शेख तौहीद, महमंत्री प्रवक्ता अमित भद्र, महमंत्री शहर प्रभारी रवि देवांगन, महामंत्री गुड्डू राव युवा कांग्रेस अध्यक्ष वोधन देवांगन प्रमोद नेलवाल, गजा पटेल महिला कांग्रेस अध्यक्ष वेदवती पात्र सुनीता मांझी, रशीला कश्यप राखी रणा, मधेश्वर जैन सभी कार्यकर्त्ता मौजूद थे।

बस्तर मुन्ने व सुशासन तिहार : क्लस्टर स्तरीय शिविर प्रारंभ

कांकेर। जिले के नागरिकों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने हेतु बस्तर संभाग में संचालित बस्तर मुन्ने तथा निवद नेल्लनार 2.0 और राज्य व्यापी सुशासन तिहार अभियान के तहत जिले के विभिन्न ग्रामों में 01 मई से शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में क्लस्टर स्तरीय शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें जनता की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है, साथ ही विभिन्न व्यक्तिमूलक योजनाओं से लाभान्वित भी किया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेश मंडावी द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार 21 मई को अंतागढ़ विकासखण्ड के ग्राम आमागांव, भानुप्रतापपुर विकासखण्ड के सोनेकन्हार, चारामा विकासखण्ड के ग्राम हल्बा, कोयलीबेड़ा के ग्राम घरमपुर, नरहरपुर विकासखण्ड के ग्राम सुरही में क्लस्टर स्तरीय शिविर का आयोजन किया जाएगा।

भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं के बच्चों से प्रधानमंत्री एवं रक्षामंत्री विवेकाधीन निधि छात्रवृत्ति हेतु आवेदन आमंत्रित

कांकेर। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना और रक्षामंत्री विवेकाधीन निधि योजनांतर्गत भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं के बच्चों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकती है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कांकेर ने बताया कि रक्षामंत्री विवेकाधीन निधि (आर.एम.डी.एफ) छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं के वे बच्चे, जिन्होंने वर्ष 2025-26 में कक्षा पहली से 12वीं अथवा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना हेतु तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं के बच्चों को लाभ दिया जाएगा। योजना हेतु पात्रता के लिए छात्र का 12वीं कक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2026 निर्धारित की गई है। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदकों को मूल दस्तावेजों के साथ प्रमाणीकरण हेतु जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में उपस्थित होना होगा। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ने बताया कि कांकेर जिले में निवासरत मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से सेवानिवृत्त अधिकारियों से भी कार्यालय में उपस्थित होकर पंजीयन एवं पहचान पत्र बनवाने की अपील की गई है।

इसके अतिरिक्त सेवारत सैनिकों से भी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में अपना नाम दर्ज कराने का आग्रह किया गया है, ताकि उन्हें राज्य शासन द्वारा प्रदत्त शासकीय सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जा सके। छात्रवृत्ति एवं अन्य जानकारियों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कांकेर के दूरभाष नंबर 07868-299299 पर संपर्क किया जा सकता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गीदम की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर जोर, एनक्यूएएस प्रमाणन की तैयारियां तेज

50 बिस्तरीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल की समीक्षा बैठक

दंतेवाड़ा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अजय रामटेके ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गीदम एवं 50 बिस्तरीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल की समीक्षा बैठक लेकर स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर संचालन एवं गुणवत्ता सुधार को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में डॉ रामटेके ने अस्पताल की ओपीडी सेवाओं का नियमित एवं व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आईपीडी में भर्ती मरीजों की नियमित देखभाल, गुणवत्तापूर्ण भोजन व्यवस्था तथा अस्पताल परिसर में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही।

साथ ही मरीजों को लैब जांच एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिए गए।

बैठक के दौरान आने वाले समय में अस्पताल को एनक्यूएएस (नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड) प्रमाणन दिलाने हेतु आवश्यक तैयारियों और कार्ययोजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने, मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने तथा अस्पताल प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर खंड चिकित्सा अधिकारी गीदम डॉ भुवन विजय कुर्रे, जिला क्वालिटी सलाहकार अंकित सिंह, डॉ सविता टागराज सहित चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

राहुल गांधी का बयान लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफः अमर अग्रवाल ने की कड़ी निंदा

बिलासपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नगर विधायक अमर अग्रवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे अत्यंत शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर आसीन नेताओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना देशवासियों की भावनाओं का अपमान है। कांग्रेस नेताओं द्वारा लगातार इस प्रकार की बयानबाजी उनकी नकारात्मक एवं द्वेषपूर्ण राजनीति को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश गर्व महसूस करता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व के 32 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुए हैं। यह भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा, मजबूत नेतृत्व और विश्व मंच पर देश की सशक्त उपस्थिति का प्रतीक है। श्री अमर अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का सम्मान प्रत्येक भारतीय का सम्मान है। उनके नेतृत्व में भारत एक मजबूत और विश्वसनीय राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। इसके बावजूद कांग्रेस द्वारा लगातार अपशब्दों का प्रयोग अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की जनता कांग्रेस की इस नकारात्मक राजनीति को पहले भी नकार चुकी है और आगे भी इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में समर वेकेशन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने समर वेकेशन के दौरान न्यायिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने और संसाधनों की बचत के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर हाई कोर्ट प्रशासन ने विशेष सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत अवकाश अवधि में मामलों की सुनवाई मुख्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। जारी परिपत्र के अनुसार, भीषण गर्मी को देखते हुए अधिवक्ताओं और पक्षकारों को अनावश्यक रूप से न्यायालय आने से राहत देने के लिए ऑनलाइन सुनवाई को प्राथमिकता दी जाएगी। हाई कोर्ट प्रशासन का मानना है कि इससे समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी, साथ ही न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित नहीं होगी। इसके अलावा हाई कोर्ट और जिला न्यायपालिका के कर्मचारियों को सप्ताह में अधिकतम दो दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि इसके लिए कार्यालयों में न्यूनतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, ताकि न्यायालयीन कार्य प्रभावित न हों। घर से कार्य करने वाले कर्मचारियों को फोन और अन्य आधिकारिक माध्यमों से लगातार उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संसाधनों और ईंधन की बचत को ध्यान में रखते हुए न्यायिक अधिकारियों, रजिस्ट्री अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कार-पूलिंग व्यवस्था अपनाने की भी सलाह दी गई है। आवश्यकता पड़ने पर न्यायाधीशों को भी इस व्यवस्था के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हाई कोर्ट प्रशासन ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित तकनीकी व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित रजिस्ट्री अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

नौकरी पाने के चक्कर में युवक पैसा गंवा बैठा, किया सुसाइड

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी और प्रताड़ना से तंग आकर युवक द्वारा आत्मघाती कदम उठाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठगों के चंगुल में फंसकर अपनी जान गंवाने वाले युवक के लाचार पिता ने अब प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद थक-हारकर कलेक्टर जनदर्शन में न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम हिरी निवासी रमेश साहू ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जनदर्शन में अपनी पीड़ा सुनाई। उन्होंने बताया कि भवानी वैष्णव ने अप्रैल 2025 में बेटे राहुल साहू को रेलवे मेस में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। इसके एवज में पीड़ित पिता ने अपनी काश्तकारी भूमि को गिरवी रखकर कुल पांच लाख रुपए नगद आरोपित दंपति को सौंपे थे। आरोपितों ने छह महीने के भीतर नौकरी लगाने का खोखला आश्वासन दिया था। समय बीतने के बाद जब नौकरी नहीं लगी, तो पीड़ित पक्ष को ठगी का अहसास हुआ। जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपित भवानी वैष्णव और उसकी पत्नी ने रुपए लौटाने से साफमना कर दिया और उल्टा राहुल को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर डराने-धमकाने लगे।

सुशासन तिहार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्राम रामपुर में जनसमस्या निवारण शिविर में की शिरकत, ग्रामीणों से किया गया सीधा संवाद.......

- 66.99 करोड़ रुपये की लागत के 87 विकास कार्यो का लोकार्पण एवं शिलान्यास, 116 हितग्राहियों को सहायता राशि एवं सामग्री प्रदाय
- जनता जनार्दन से मिलकर मिलती है काम करने की नई ऊर्जा- मुख्यमंत्री'

सूरजपुर। संवाददाता मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज जनपद पंचायत रामानुजनगर के ग्राम रामपुर में आयोजित सुशासन तिहार के अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविर में शिरकत कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया तथा उनकी समस्याएं धैर्यपूर्वक सुनीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 66.99 करोड़ रुपये की लागत के कुल 87 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को महत्वपूर्ण सौगात प्रदान की। उन्होंने शिविर स्थल पर लगे विभिन्न विभागीय स्टॉलों का अवलोकन कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली तथा 116 हितग्राहियों को सहायता राशि एवं सामग्री का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति प्रबल जनभागीदारी एवं शासन के प्रति अटूट विश्वास को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि जनता ने सरकार बनाई है और सरकार स्वयं जनता के बीच पहुंचकर यह जानने का प्रयास कर रही है कि शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सही ढंग से पहुंच रहा है या नहीं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सूरजपुर का यह उनका 11वां जिला प्रवास है तथा 10 जून तक प्रदेश के सभी 33 जिलों के दौरे का लक्ष्य निर्धारित है। प्रत्येक जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन, राजस्व प्रकरणों के निराकरण एवं लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही है तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ही समस्याओं का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। औचक निरीक्षण के माध्यम से व्यवस्थाओं की सतत निगरानी भी की जा रही है तथा नागरिक सुविधाओं के मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने तेन्दूपत्ता संग्राहक माताओं-बहनों को चरण पादुका योजना के तहत वितरित किए जा रहे जूतों का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व में ग्रामीण नंगे पैर जंगल जाते थे, अब इस योजना से उन्हें बड़ी राहत मिल रही है। उन्होंने किसानों को 3716 करोड़ रुपये बोनस वितरण का उल्लेख करते हुए बताया कि सरकार बनने के बाद 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं, किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है तथा लगभग 70 लाख माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित महिलाओं से योजना की राशि नियमित रूप से प्राप्त होने की जानकारी भी ली।

ट्रेनों में आगजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु बिलासपुर रेल मंडल में विशेष संरक्षा अभियान

- संरक्षा विभाग की सक्रिय पहल : फायर सेफ्टी सिस्टम एवं प्रशिक्षण पर विशेष जोर

बिलासपुर। बिलासपुर रेल मंडल के संरक्षा विभाग द्वारा ट्रेनों में आगजनी की संभावित घटनाओं की रोकथाम, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा रेल संपत्ति की संरक्षा के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर विशेष संरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान मंडल के विभिन्न प्रमुख स्टेशनों एवं गुजरने वाली ट्रेनों में युद्धस्तर पर संचालित किया जा रहा है। बिलासपुर रेल मंडल से गुजरने वाली सभी मेल/एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एवं यात्री ट्रेनों सहित मंडल से प्रारंभ होने वाली ट्रेनों में विशेष संरक्षा जांच एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान संरक्षा विभाग द्वारा कोचों, पावर कार, पैंट्री कार एवं अन्य संवेदनशील स्थानों का गहन निरीक्षण किया गया। अभियान के अंतर्गत एसी कोचों में फायर एक्सटिंग्विशर की उपलब्धता एवं कार्यशीलता की जांच, फायर डिटेक्शन एवं सप्रेशन सिस्टम (एफडीएसएस/एसएफडीएस) की जांच, पावर कारों में विद्युत सुरक्षा संबंधी निरीक्षण, वायरिंग चेक, अर्थ लीकेज चेक, एमसीबी एवं विद्युत पैनलों की जांच, थर्मल स्कैनिंग, बैटरी एवं जंक्शन बॉक्स की जांच जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इसके अतिरिक्त पैंट्री कार एवं पावर कार में फायर डिटेक्शन एवं फायर सप्रेशन सिस्टम की उपलब्धता एवं कार्यशीलता सुनिश्चित की गई। ट्रेनों में अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, फायर बॉल एवं एयरोसोल आधारित अग्निशमन प्रणाली, अग्निशमन यंत्रों की वैधता एवं उपयोगिता की भी विशेष जांच की गई। संरक्षा विभाग द्वारा ऑन बोर्ड स्टाफ कोच अटेंडेंट, टीटीई, पैंट्री कार स्टाफ एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों को फायर फाइटिंग, आपातकालीन प्रतिक्रिया, यात्रियों की सुरक्षित निकासी एवं प्रारंभिक अग्निशमन संबंधी विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

छत्तीसगढ़िया क्रांतिसेना और जेसीपी प्रमुख अमित बघेल की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

बिलासपुर। बलौदाबाजार आगजनी कांड मामले में गिरफ्तार छत्तीसगढ़िया क्रांतिसेना और जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से झटका लगा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे अमित की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बलौदा बाजार कोतवाली पुलिस ने अमित बघेल को आगजनी और हिंसा से जुड़े अलग-अलग मामलों में विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पहले निचली अदालत में जमानत की मांग की थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने पर हाईकोर्ट का रुख किया। अब हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, यह पूरा मामला बलौदा बाजार हिंसा कांड से जुड़ा है। 15 और 16 मई 2024 की रात गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। इस घटना के विरोध में 10 जून को हजारों लोग बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए थे। प्रदर्शन के दौरान स्थिति हिंसक हो गई और उपद्रवियों ने कलेक्टर व एसपी कार्यालय में आग लगा दी थी। इस आगजनी में सरकारी संपत्तियों को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा था। इसी मामले में पुलिस ने अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की थी। याचिका में अन्य आरोपियों को मिली जमानत का हवाला देते हुए समानता के आधार पर राहत देने की मांग की गई थी। हालांकि मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अमित बघेल को राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि मामले में अन्य आरोपियों से उनकी स्थिति अलग है, उनके खिलाफ कई अन्य आपराधिक मामले भी लंबित हैं। इसी आधार पर अदालत ने समानता का दावा स्वीकार नहीं किया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि अमित बघेल के खिलाफ कुल 17 मामले लंबित हैं। वहीं सह आरोपी अजय यादव के खिलाफ 13 और दिनेश कुमार वर्मा के खिलाफ एक अन्य मामला दर्ज है। अदालत ने कहा कि लंबित मामलों और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि मामले में संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी हो जाती है या आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि पूरी हो जाती है, तो आरोपी दोबारा जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। अदालत के इस फैसले के बाद अमित बघेल को अब जेल में ही रहना होगा।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में समर वेकेशन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने समर वेकेशन के दौरान न्यायिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने और संसाधनों की बचत के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर हाई कोर्ट प्रशासन ने विशेष सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत अवकाश अवधि में मामलों की सुनवाई मुख्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। जारी परिपत्र के अनुसार, भीषण गर्मी को देखते हुए अधिवक्ताओं और पक्षकारों को अनावश्यक रूप से न्यायालय आने से राहत देने के लिए ऑनलाइन सुनवाई को प्राथमिकता दी जाएगी। हाई कोर्ट प्रशासन का मानना है कि इससे समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी, साथ ही न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित नहीं होगी। इसके अलावा हाई कोर्ट और जिला न्यायपालिका के कर्मचारियों को सप्ताह में अधिकतम दो दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि इसके लिए कार्यालयों में न्यूनतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, ताकि न्यायालयीन कार्य प्रभावित न हों। घर से कार्य करने वाले कर्मचारियों को फोन और अन्य आधिकारिक माध्यमों से लगातार उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संसाधनों और ईंधन की बचत को ध्यान में रखते हुए न्यायिक अधिकारियों, रजिस्ट्री अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कार-पूलिंग व्यवस्था अपनाने की भी सलाह दी गई है। आवश्यकता पड़ने पर न्यायाधीशों को भी इस व्यवस्था के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने बढ़ाया दिव्यांग बेटी का हौसला एक व्हील चेयर ने कम कर दी मां की वर्षों पुरानी चिंता....

- व्हील चेयर मिलने से बदली दिव्यांग बेटी की जिंदगी मां की आंखों में छलक आई राहत

सूरजपुर संवाददाता। रामपुर शिविर में उस समय भावुक दृश्य देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ग्राम पंचायत सरईपारा निवासी 17 वर्षीय दिव्यांग बालिका रोशनी को व्हील चेयर प्रदान की। वर्षों से बेटी को गोद में उठाकर इधर-उधर ले जाने वाली मां अनीता कुर्रे की आंखों में उस समय राहत और खुशी साफदिखाई दे रही थी। रोशनी जन्म से ही दिव्यांग है। वह बहुत कम सुन पाती है और बोल भी नहीं पाती। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए उसकी देखभाल करना आसान नहीं था। मां अनीता और परिवार के अन्य सदस्य उसे गोद में उठाकर ही हर जगह ले जाया करते थे। घर से बाहर ले जाना हो या अस्पताल, हर बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने जब शिविर में रोशनी और उसकी मां से मुलाकात की, तो उनकी परिस्थितियों को गंभीरता से सुना। इसके बाद उन्होंने तत्काल रोशनी को व्हील चेयर प्रदान की। व्हील चेयर मिलते ही रोशनी के मां के चेहरे पर राहत थी। रोशनी की मां अनीता कुर्रे ने बताया कि उनका परिवार मजदूरी कर घर का खर्च चलाता है। सीमित आय में बेटी की देखभाल और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना काफी मुश्किल था। उन्होंने भावुक होकर कहा कि अब व्हील चेयर मिलने से रोशनी को कहीं भी ले जाना आसान हो जाएगा और उसकी जिंदगी कुछ हद तक सहज बन सकेगी। अनीता ने मुख्यमंत्री और शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मदद उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा सहारा है। उन्होंने कहा कि पहले जहां हर कदम पर परेशानी होती थी, वहीं अब बेटी को संभालने में काफी सुविधा मिलेगी। रामपुर शिविर में संवेदनशील शासन व्यवस्था की तस्वीर थी, जहां जरूरतमंदों की कठिनाइयों को समझते हुए उन्हें राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी बेटी के लिए मां की आंखों की राहत इस बात का प्रमाण थी कि छोटी-सी मदद भी किसी परिवार के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है।

कलेक्टर का बिहारपुर अंचल में सघन निरीक्षण दौरा, धरातल पर परखी विकास कार्यों की गुणवत्ता

- पूरक पोषण आहार केंद्र से लेकर एकलव्य विद्यालय तक का किया निरीक्षण
- बांक पर्यटन स्थल के विकास की संभावनाओं पर भी हुआ मंथन

सूरजपुर। कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने आज जिले के दूरस्थ अंचल बिहारपुर का सघन दौरा कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की धरातलीय हकीकत स्वयं परखी। प्रातः से प्रारंभ हुए इस मैराथन दौरे में कलेक्टर ने पूरक पोषण आहार उत्पादन केंद्र, नवनिर्मित महतारी सदन, नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अंतर्राज्यीय पुलिस चौकी नवाटोला , निर्माणाधीन एकलव्य विद्यालय एवं बांक पर्यटन स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने एक-एक तथ्य का गहन आकलन किया तथा जहां भी कमियां पाई गईं, वहां संबंधितों को मौके पर ही कमियों को दूर करने के कड़े निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती जमील ने अपने दौरे की शुरुआत ग्राम करकोटु, भैयाथान स्थित पूरक पोषण आहार उत्पादन केंद्र से की। केंद्र में उन्होंने दलिया एवं अन्य पोषण उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन किया तथा कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर तैयार उत्पादों के वितरण तक की समूची व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि केंद्र से निर्मित होने वाले प्रत्येक उत्पाद की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही उत्पादन सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि यह पोषण आहार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं तक पहुंचता है, अतः इसकी गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात कलेक्टर ने ग्राम पंचायत ठाढ़पाथर, ओड़गी में नवनिर्मित महतारी सदन का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में सामने आई कमियों को चिन्हित करते हुए उन्होंने संबंधितों को निर्देशित किया कि शीघ्रातिशीघ्र सभी आवश्यक सुधार कार्य पूर्ण कराए जाएं। दौरे के क्रम में कलेक्टर श्रीमती जमील ने निर्माणाधीन नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारपुर के भवन निर्माण कार्य का गहन निरीक्षण किया। निर्माण में पाई गई कमियों पर उन्होंने ठेकेदार को निश्चित समय-सीमा के भीतर सुधार कार्य पूर्ण करने तथा शेष निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ सम्पन्न कराने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण मानकों के कड़ाई से पालन करने की बात कही। अपने दौरे के अगले चरण में कलेक्टर श्रीमती जमील की गाड़ी अंतर्राज्यीय पुलिस चौकी नवाटोला तक पहुंची, जहां उन्होंने चौकी की समस्त व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी कैमरे कार्यरत न पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कैमरे तत्काल दुरुस्त कराए जाएं तथा चौकी की सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहां सतर्क निगरानी एवं चाक-चौबंद सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं है। कलेक्टर ने पालदनौली में निर्माणाधीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का भी विस्तार से निरीक्षण किया। निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित ठेकेदार को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण दौरे के अंतिम चरण में कलेक्टर ने जिले के बांक पर्यटन स्थल का भ्रमण किया। उन्होंने रेण नदी पर स्थित मनोरम झरने का अवलोकन किया तथा पर्यटन की दृष्टि से बांक को और अधिक विकसित किए जाने की संभावनाओं पर उपस्थित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के पर्यटन स्थलों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए एक प्रभावी एवं सुनियोजित प्रचार-प्रसार कार्ययोजना तैयार की जाए।

आबकारी अफसर की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र की जांच शुरू

बिलासपुर। आबकारी अधिकारी के फर्जी जाति प्रमाणपत्र बनवाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट ने बिलासपुर की जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति को जल्द जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। आबकारी अफसर राजेश हेनरी पर आरोप है कि बिलासपुर में बने फर्जी प्रमाणपत्र के जरिए वह पिछले 35 साल से आबकारी विभाग में नौकरी कर रहे हैं. इस मामले में भोपाल निवासी प्रभात पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें बताया कि मध्यप्रदेश के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त राजेश हेनरी ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की है. उन्होंने इस संबंध में 22 जून 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन लंबे समय से यह मामला बिलासपुर की जिला स्तरीय जाति सत्यापन समिति के पास लंबित है. याचिका में बताया गया कि सूचना के अधिकार के तहत ली गई जानकारी के अनुसार उक्त अधिकारी के प्रमाणपत्र में बिलासपुर तहसील के सील और साइन मिले. लेकिन, जब बिलासपुर तहसील कोर्ट के दायरा पंजी में साल 1990-91 के प्रकरण की जानकारी ली गई, तब पता चला कि तहसील कार्यालय में उनके जाति प्रमाण पत्र का प्रकरण ही दर्ज नहीं है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि, छत्तीसगढ़ की उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने उनके अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाणपत्र को जांच के लिए जिला स्तरीय समिति को भेजा था. लेकिन, दो साल से अफसर जांच ही नहीं कर रहे.

शरीर के टाइप के हिसाब से करें जींस का चयन

आज के फैशन ट्रेंड में जींस हर उम्र के लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है, लेकिन सही जींस चुनना हमेशा आसान नहीं होता। अक्सर लोग सिर्फ डिजाइन या ट्रेंड देखकर जींस खरीद लेते हैं, जो उनके शरीर के टाइप पर फिट नहीं बैठती और लुक खराब कर देती है। फैशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, हर व्यक्ति का बॉडी टाइप अलग होता है और उसी के हिसाब से जींस का चयन करना चाहिए। खासतौर पर महिलाओं को तो इसका खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सही फिटिंग की जींस न केवल आपके लुक को स्टाइलिश बनाती है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। आजकल मार्केट में स्किनी, स्ट्रेट, बूटकट और रिलैक्स्ड फिट जैसी कई वैरायटी मौजूद हैं। अगर आप अपने बॉडी शेप को समझकर जींस चुनते हैं, तो आपका ओवरऑल लुक और भी आकर्षक दिखता है। यही वजह है कि फैशन की दुनिया में "बॉडी टाइप बेस्ड डेनिम" एक नया ट्रेंड बन गया है।

1. स्लिम बॉडी टाइप

अगर आपका शरीर स्लिम है, तो आपको ऐसी जींस चुननी चाहिए जो आपके फिगर को थोड़ा डिफाइन और बैलेंस दिखाए। स्किनी फिट या स्लिम फिट जींस इस बॉडी टाइप पर काफी अच्छी लगती है क्योंकि यह पैरों को शेप देकर लुक को स्मार्ट बनाती है। हल्के स्ट्रेच वाली डेनिम भी बेहतर रहती है ताकि मूवमेंट आरामदायक रहे। बहुत ज्यादा ढीली जींस पहनने से लुक और पतला दिख सकता है, इसलिए फिटेड स्टाइल ज्यादा उपयुक्त माना जाता है।

2. कर्वी बॉडी टाइप

कर्वी बॉडी टाइप के लिए ऐसी जींस चुननी चाहिए जो कमर और हिप्स को सही तरह से सपोर्ट दे। हाई-वेस्ट स्ट्रेट फिट या बूटकट जींस इस बॉडी शेप पर सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि यह शरीर के कर्व्स को बैलेंस करती है और एक स्मूथ सिल्हूट देती है। स्ट्रेच डेनिम वाली जींस पहनने से आराम भी मिलता है और फिटिंग भी बेहतर रहती है। बहुत टाइट स्किनी जींस से बचना चाहिए, क्योंकि इससे अनकंफर्टेबल फील हो सकता है।

3. एथलेटिक बॉडी टाइप

एथलेटिक बॉडी में शरीर फिट और मस्कुलर होता है, इसलिए ऐसी जींस चुननी चाहिए जो बॉडी के साथ बैलेंस बनाए रखे। रिलैक्स्ड फिट या टेपर जींस इस बॉडी टाइप के लिए परफेक्ट रहती है। यह लुक को न तो बहुत टाइट बनाती है और न ही बहुत ढीला, जिससे एक स्मार्ट और क्लीन अपीयरेंस मिलता है। हल्के डार्क शेड्स की डेनिम भी इस बॉडी टाइप पर काफी अच्छी लगती है और स्टाइल को और बेहतर बनाती है।

4. रेक्टेंगल बॉडी टाइप

इस बॉडी शेप में कमर कम डिफाइंड होती है और शरीर लगभग सीधा दिखता है। ऐसे में फ्लेयर्ड या हाई-वेस्ट जींस पहनने से कमर को शेप मिलता है और एक कर्वी इफेक्ट क्रिएट होता है। यह स्टाइल शरीर को ज्यादा बैलेंस्ड और स्टाइलिश दिखाता है। हल्की बेल बॉटम या वाइड लेग जींस भी इस बॉडी टाइप के लिए अच्छी रहती है क्योंकि यह लुक में डाइमेंशन जोड़ती है।

भूलकर भी घर में न लगाएं ये पौधे

घर में लगे पौधे सिर्फ सजावट का हिस्सा नहीं होते, ये हमारे आसपास की ऊर्जा को प्रभावित भी करते हैं। कई लोग हरियाली बढ़ाने के लिए तरह-तरह के पौधे लगा लेते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार हर पौधा घर के लिए शुभ नहीं होता। कुछ पौधे ऐसे भी माने जाते हैं, जो अनजाने में नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकते हैं और घर के माहौल को प्रभावित कर देते हैं। मान्यता है कि ऐसे पौधे परिवार में तनाव, रुकावट और आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि सही जानकारी के साथ ही पौधों का चयन किया जाए। आइए जानते हैं किन पौधों को घर में लगाने से बचना चाहिए।

बोन्साई पौधा

बोन्साई देखने में आकर्षक जरूर लगता है, लेकिन इसे घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि यह पौधा जीवन में प्रगति को सीमित कर देता है और करियर की गति को धीमा कर सकता है।

इमली का पेड़

इमली का पौधा या पेड़ घर के भीतर या आसपास लगाना भी अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है, जिससे घर में परेशानी बढ़ सकती है।

दूध निकलने वाले पौधे

ऐसे पौधे जिनसे दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है, उन्हें भी घर में लगाने से बचना चाहिए। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, ये पौधे आर्थिक तंगी और कर्ज बढ़ने का कारण बन सकते हैं।

सूखे या मुरझाए पौधे

घर में सूखे या खराब हो चुके पौधों को रखना भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे पौधे नकारात्मकता का संकेत होते हैं और जीवन में रुकावटें ला सकते हैं। इसलिए इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए।

घर में कौन से पौधे लगाना शुभ होता है?

वास्तु के अनुसार, कुछ पौधे सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। जैसे तुलसी, मनी प्लांट, जेड प्लांट, स्नेक प्लांट और शमी का पौधा। ये पौधे घर में सुख-शांति और खुशहाली लाने में सहायक माने जाते हैं।

काटने के कितने देर बाद खराब हो जाते हैं फल?

क्यों खतरनाक हो सकते हैं कटे फल?

दरअसल, जैसे ही हम किसी फल को काटते हैं, वह बाहर की हवा, नमी और कीटाणुओं के संपर्क में आने लगते हैं। इसलिए कटे हुए फल पर साल्मोनेला, लिस्टेरिया और ई। कोलाई जैसे हानिकारक बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है। फ्रिज इन बैक्टीरिया के पनपने की गति को धीमा तो करता है, लेकिन उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं करता। साथ ही, हवा के संपर्क में आने से फलों में ऑक्सीडाइजेशन शुरू हो जाता है, जिससे विटामिन-सी जैसे पोषक तत्व कम होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि सेब या केला कटने के कुछ देर बाद भूरा होने लगता है, यह इसी प्रक्रिया का संकेत है।

कितने घंटे तक ठीक रहते हैं कटे फल?

फलों की ताजगी और सुरक्षा उनके प्रकार और तापमान पर निर्भर करती है। अगर कटे हुए फल बाहर रखे हैं, तो उन्हें 4 से 6 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। अगर फ्रिज का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, तो कटे हुए ज्यादातर फल 24 घंटे तक सुरक्षित माने जाते हैं।

स्टोर करने के दौरान होने वाली आम गलतियां

अक्सर लोग फलों को प्लेट में खुला छोड़ देते हैं या उन्हें एल्युमिनियम फॉयल में ढीला लपेटकर रख देते हैं। बार-बार फ्रिज का दरवाजा खोलने से तापमान में उतार-चढ़ाव होता है, जिससे फलों की गुणवत्ता गिरती है। हर बार जब आप कंटेनर खोलते हैं, तो दूषित हवा अंदर जाती है, जो फल को खराब करने की प्रक्रिया तेज कर देती है।

सुरक्षित रखने के सही तरीके

अगर आपको फल काटकर रखना ही है, तो इन नियमों का पालन करें-

एयरटाइट कंटेनर- फलों को हमेशा कांच के एयरटाइट कंटेनर में रखें। यह हवा के संपर्क को कम करता है और गंध को फल में जाने से रोकता है।

स्वच्छता- फल काटने से पहले हाथ, चाकू और कटिंग बोर्ड को अच्छी तरह धोएं। गंदे चाकू से फल काटने पर बैक्टीरिया तुरंत अंदर तक पहुंच जाते हैं।

रेफ्रिजरेशन- फल काटने के तुरंत बाद उन्हें फ्रिज में रख दें।

खराब फल की पहचान कैसे करें?

कभी-कभी फल 24 घंटे के भीतर भी खराब हो सकते हैं।

तरबूज, खरबूजा, पपीता और अनानास जैसे फल जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, वे जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि इनमें नमी के कारण बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैलते हैं।

इन संकेतों पर ध्यान दें-

अगर फल से फर्मेंटेशन जैसी खट्टी गंध आ रही है। अगर फल चिपचिपा हो गया है या बहुत ज्यादा पानी छोड़ रहा है। अगर फल का रंग बहुत गहरा या काला पड़ गया है।

आज का राशिफल

मेष राशि - आपके लिए सुख-सुविधाओं और पारिवारिक मजबूती का रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा अपनी स्वराशि में स्थित है। प्रथम भाव में मंगल की उपस्थिति आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। करियर में प्रमोशन के योग हैं और कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी। बिजनेस में नई योजनाओं पर अमल करना लाभदायक रहेगा, जिससे आर्थिक लाभ सुनिश्चित होगा। लव लाइफ में आकर्षण बढ़ेगा और दांपत्य जीवन में सुखद स्थिरता आएगी।

वृषभ राशि - आपके लिए पराक्रम और संवाद कौशल में सफलता लेकर आएगा, क्योंकि आपकी राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। आपकी राशि में सूर्य-बुध की उपस्थिति करियर में आपकी बौद्धिक क्षमता को निखारेगी। नौकरी में नए अवसर मिलेंगे और व्यापार में प्रतिस्पर्धा के बावजूद आप तरक्की करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हालांकि निवेश से पहले अनुभवी की सलाह जरूर लें। प्रेम प्रसंगों में मधुरता रहेगी और पार्टनर के साथ छोटी यात्रा के योग हैं।

मिथुन राशि - आपके लिए धन संचय और पारिवारिक खुशियों का है, क्योंकि आपकी राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का संचरण हो रहा है। आपकी राशि में गुरु और शुक्र की युति करियर में असाधारण प्रगति और पदोन्नति के द्वार खोलेगी। बिजनेस में बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावना है, जिससे आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे। लव लाइफ में रोमांस चरम पर रहेगा और अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।

कर्क राशि - आपकी राशि के प्रथम भाव में चंद्रमा अपनी स्वराशि में विराजमान हैं। यह गोचर आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। करियर में आपकी मेहनत रंग लाएगी और महत्वपूर्ण निर्णयों में सफलता मिलेगी। व्यापार में तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे और आर्थिक लाभ संतोषजनक रहेगा। लव लाइफ में पार्टनर के प्रति समर्पण बढ़ेगा, जिससे रिश्ते में मजबूती आएगी।

सिंह राशि - आपके लिए खर्चों और बाहरी संपर्कों पर ध्यान देने का है, क्योंकि आपकी राशि के द्वादश भाव में चंद्रमा स्थित है। करियर के क्षेत्र में कार्यभार अधिक रह सकता है, जिससे मानसिक तनाव संभव है। बिजनेस में कोई भी जोखिम भरा निवेश करने से बचें, आर्थिक हानि के संकेत हैं। विरोधियों की प्रतिस्पर्धा आपको नई रणनीतियां बनाने पर मजबूर करेगी।

कन्या राशि - आपके लिए लाभ और खुशियों की नई किरण लेकर आएगा, क्योंकि आपकी राशि के एकादश भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे और आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। बिजनेस में बड़े लाभ के योग हैं और नए संपर्कों से आय बढ़ेगी। निवेश के लिए समय बहुत अनुकूल है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और पार्टनर के साथ आप किसी सुखद भविष्य की योजना बनाएंगे। दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा।

तुला राशि-आपके लिए करियर में मान-सम्मान और अधिकार प्राप्ति का है, क्योंकि आपकी राशि के दशम भाव में चंद्रमा का संचरण हो रहा है। नौकरी में आपके काम की गुणवत्ता आपको प्रमोशन की ओर ले जा सकती है। बिजनेस में स्थिरता आएगी और पुराने निवेशों से आर्थिक लाभ होगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लव लाइफ में पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, जिससे दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।

वृश्चिक राशि – आपके लिए भाग्य की उन्नति और नई संभावनाओं का रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के नवम भाव में चंद्रमा अपनी स्वराशि में हैं। करियर में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे और लंबी दूरी की यात्राएं सफल होंगी। बिजनेस में नई शुरुआत करना लाभदायक रहेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा और आप पार्टनर के साथ गहरा लगाव महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के योग हैं।

धनु राशि– आपके लिए धैर्य और संयम बरतने का है, क्योंकि आपकी राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। करियर में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है। बिजनेस में उधारी के लेनदेन से बचें, आर्थिक हानि की संभावना है। रिश्तों में छोटी-छोटी बातों पर तनाव हो सकता है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें।

मकर राशि - आपके लिए साझेदारी और मधुर रिश्तों का होगा, क्योंकि आपकी राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। बिजनेस में नए अनुबंध हो सकते हैं, जो भविष्य में तरक्की दिलाएंगे। नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन भविष्य के लिए निवेश की योजना बनेगी। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा और दांपत्य जीवन में आकर्षण बना रहेगा।

कुंभ राशि- आपके लिए अनुशासन और विरोधियों पर विजय पाने का है, क्योंकि आपकी राशि के छठे भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। करियर में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद आप अपनी मेहनत और लगन से सफलता हासिल करेंगे। नौकरी में आपके काम की बारीकियों पर ध्यान दिया जाएगा। आर्थिक लाभ के लिए मेहनत अधिक करनी होगी, लेकिन सफलता निश्चित है।

मीन राशि- आपके लिए रचनात्मकता और खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के पंचम भाव में चंद्रमा अपनी स्वराशि में स्थित हैं। करियर में आपके नवाचारों की सराहना होगी और नई शुरुआत के लिए बेहतरीन अवसर मिलेंगे। बिजनेस में प्रगति होगी और निवेश से अच्छा लाभ होने के योग हैं। लव लाइफ में प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी और पार्टनर के साथ रिश्ते और गहरे होंगे।

आलू उबालते वक्त कुकर में डाल दीजिए ये 5 चीजें

छीलने में नहीं होगी परेशानी

हमारे यहां खाने-पीने की बात हो और आलू का जिक्र न हो, ऐसा नामुमकिन है। अधिकतर लोग आलू सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसे कई तरह की सब्जियों में डाला जाता है और कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। आलू से बनी सब्जी, पराठा, टिक्की, चाट, सैंडविच और स्नैक्स लगभग हर घर में पसंद किए जाते हैं। कई बार आलू उबालने के बाद उनका छिलका आसानी से नहीं उतरता या फिर उनका स्वाद फीका लगने लगता है। अगर आलू उबालते समय कुकर में कुछ खास चीजें डाल दी जाएं, तो आलू न सिर्फ अच्छे से उबलते हैं, बल्कि उनका स्वाद और टेक्सचर भी बेहतर हो सकता है।

नमक डालने से आलू बनेंगे टेस्टी

आलू उबालते समय पानी में थोड़ा नमक डालना एक बेहद आसान, लेकिन असरदार तरीका माना जाता है। नमक उबलते पानी के साथ आलू के अंदर तक पहुंच सकता है, जिससे आलू हल्के नमकीन और ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। नमक डालने से आलू का छिलका थोड़ा ढीला हो जाता है, जिससे उसे उतारना आसान हो सकता है। खासकर अगर आलू बड़े आकार के हों, तो यह तरीका काफी काम आ सकता है।

एक चम्मच तेल करेगा कमाल

आलू उबालते समय कुकर में एक छोटा चम्मच तेल डालना भी फायदेमंद माना जाता है। तेल आलू की ऊपरी सतह पर हल्की परत बना सकता है, जिससे उबलने के बाद छिलका आसानी से अलग होने लगता है। तेल डालने से आलू ज्यादा फटते या टूटते नहीं हैं। अगर आप आलू का इस्तेमाल सलाद, चाट या टिक्की जैसी डिश में करना चाहते हैं, जहां आलू का सही आकार बनाए रखना जरूरी होता है, तो यह ट्रिक आपके काफी काम आ सकती है।

नींबू का रस सुधारेगा स्वाद

कुछ लोग आलू उबालते समय पानी में थोड़ा सा नींबू रस डालते हैं। माना जाता है कि इससे आलू का रंग ज्यादा अच्छा बना रहता है और उबालने के बाद उनका छिलका जल्दी निकल सकता है। नींबू की हल्की खटास आलू के स्वाद को भी थोड़ा बेहतर बना सकती है। खासकर अगर आप उबले आलू से सलाद या स्नैक्स तैयार कर रहे हैं, तो यह तरीका स्वाद में हल्का ट्विस्ट ला सकता है।

गर्मी में दही खाने से मिलती है ठंडक

दही भारतीय खान-पान का एक अहम हिस्सा है, जो स्वाद और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद माना जाता है। लोग इसे अलग-अलग तरीके से खाते हैं, किसी को नमकीन दही (रायता या छाछ) पसंद है, तो कोई मीठा दही (चीनी, मिश्री या शहद वाला) खाना पसंद करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस स्थिति में कौन-सा दही ज्यादा अच्छा है और किसे कब लेना चाहिए। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।

नमकीन दही (रायता या छाछ)

कब खाना चाहिए?

दोपहर के भोजन के साथ। गर्मियों में रोजाना। मसालेदार या भारी खाने के साथ।

पाचन के लिए बेहतरीन : यह आंतों में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाता है और खाना जल्दी पचने में मदद करता है।

गर्मी से राहत : नमकीन दही या छाछ शरीर को ठंडा रखती है और लू से बचाने में मदद करती है।

इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस : नमक और मसाले शरीर में पानी और खनिजों का संतुलन बनाए रखते हैं।

गैस और एसिडिटी में राहत : खासकर भारी या तला-भुना खाने के बाद यह बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए, अगर आपने चावल, बिरयानी, पराठा या मसालेदार सब्जी खाई है, तो नमकीन दही सबसे अच्छा विकल्प है।

मीठा दही कब खाना चाहिए?

सुबह खाली पेट या नाश्ते में। कमजोरी या थकान होने पर।बच्चों और बुजुर्गों के लिए।

इसके फायदे

मीठा दही शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाला होता है। इसमें चीनी या शहद मिलाने से शरीर को तुरंत शक्ति मिलती है।मूड बेहतर करता है : मीठा स्वाद दिमाग को सुकून देता है और स्ट्रेस कम करता है। मीठा दही पेट को ठंडक देता है और हल्की भूख में अच्छा लगता है। जो बच्चे खट्टा दही नहीं खा पाते, उनके लिए मीठा दही बेहतर विकल्प है।

विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य हेतु करियर काउंसलिंग

विद्यार्थियों को भविष्य की विभिन्न करियर संभावनाओं से अवगत कराने तथा उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से श्री नागरदास डी. भुता चैरिटेबल ट्रस्ट एवं श्री कपोल उत्कर्ष मंडल (विलेपार्ले) के संयुक्त तत्वावधान में रविवार, 17 मई को जे.एन. भुता हॉल (श्री नागरदास डी भुता हाई स्कूल) अंधेरी पूर्व में निःशुल्क करियर काउंसलिंग एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही तथा पूरा सभागार विद्यार्थियों से खचाखच भरा रहा।कार्यक्रम में सामाजिक एवं राजनीतिक नेता श्री बिमल भुता ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध विभिन्न शैक्षणिक

योजनाओं, छात्रवृत्तियों एवं करियर विकास से जुड़ी सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को नई संभावनाओं को तलाशने, अपने कौशल को विकसित करने तथा बदलते समय के अनुसार करियर का चयन करने के लिए प्रेरित किया।इस अवसर पर प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं श्री नागरदास डी. भुता स्कूल के ट्रस्टी श्री शुभेंदुजी भुता ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में केवल पारंपरिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि कौशल विकास, आत्मविश्वास एवं सही मार्गदर्शन भी सफलता की कुंजी है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने का आह्वान किया तथा कहा कि ऐसे मार्गदर्शन कार्यक्रम विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।श्री कपोल उत्कर्ष मंडल के पदाधिकारी श्री विजय मेहता एवं श्री पंकज संघवी ने भी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि संस्था विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने विद्यार्थियों को आगे भी करियर काउंसलिंग, मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, जिससे विद्यार्थी सही दिशा में अपने भविष्य का निर्माण कर सकें।इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए उद्योग विशेषज्ञों एवं शिक्षाविदों ने भी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया। विशेषज्ञों ने मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती तकनीकों, व्यावसायिक शिक्षा तथा अन्य आधुनिक करियर विकल्पों पर विस्तार से जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को समयानुकूल शिक्षा एवं कौशल विकास का महत्व समझाया।कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने विशेषज्ञों से अपने प्रश्न पूछकर करियर संबंधी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। आयोजन को विद्यार्थियों एवं अभिभावकों द्वारा अत्यंत उपयोगी, ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी बताया गया।

रेमने में सुशासन तिहार शिविर का हुआ आयोजन

ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की दी जानकारी

जशपुरनगर। ग्राम पंचायत रेमने के ग्राम गेड़ई में कलेक्टर के निर्देशन में सुशासन तिहार का आयोजन किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित सुशासन शिविर 2026 का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा योजनाओं की जानकारी 15 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों को दिया विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ली तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त किया इस सुशासन तिहार शिविर कुल आवेदन 165 प्राप्त हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सोनक्यारी मंडल अध्यक्ष प्रभाकर यादव, महामंत्री राधेश्याम यादव, मनोरा मण्डल अध्यक्ष पंकज कुमार जायसवाल जी, महामंत्री रामदास यादवजी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सोनक्यारी मण्डल अध्यक्ष परिन्दा गुप्ता , उपाध्यक्ष संतपाल भगत ,रतनलाल नागवंसी, सुखनाथ राम, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी रघुनाथ राम, तहसीलदार मनोरा नीतू भगत जी,विकाश खंड शिक्षा अधिकारी तरुण पटेल, कृषि विभाग अधिकारी गोविंद राम चौहान मुख्य चिकित्सा अधिकारी रोशन बरियार एवं जिला प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे जिसमें प्रधानमंत्री आवास के पात्र हितग्राही को आवास की चाबी दिया गया राजस्व विभाग के द्वारा बी -1 प्रदाय किया गया कृषि विभाग के द्वारा केसीसी प्रदाय किया गया वन विभाग के द्वारा पौधे प्रदाय किया उद्यान विभाग के द्वारा फलदार पौधे प्रदाय किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ बोर्ड में उत्तीर्ण बच्चे और बच्चियों को प्रोत्साहन के स्वरूप में पुरस्कार प्रदाय किया गया और स्कूल के छोटे बच्चों को जाति निवास भी प्रदाय किया गया खाद्य विभाग के द्वारा नए राशन कार्ड प्रदाय किया गया।

सौ करोड़ की जमीन पर अवैध प्लाटिंग: 150 एकड़ जमीन पर मनमानी, दीवार, गेट और रिसोर्ट किए जमींदोज

जिलेभर में चल रहा अवैध प्लाटिंग का खेल, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

मनगटा में चला सरकारी बुलडोजर, वर्तमान में 55 से 65 लाख प्रति एकड़ का रेट

राजनांदगांव। सोमनी से लगे ग्राम मनगटा में जिला प्रशासन ने अवैध कालोनाइजरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 एकड़ में की जा रही प्लाटिंग पर बुलडोजर चला दिया। बाजार मूल्य से आंकलन किया जाए तो मनगटा चूंकि पर्यटन स्थल है, इसलिए यहां प्रति एकड़ 55 से 65 लाख रुपए का रेट है। इस हिसाब से 100 करोड़ के प्रोजेक्ट पर प्रशासनिक डंडा चला है। वहीं वर्ग फुट में इसका दाम अधिक होगा, लेकिन प्रति एकड़ भी आंका जाए तो बड़े स्तर पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी, जिस पर सख्ती बरती गई है। एसडीएम गौतम पाटिल ने बताया कि सूचना प्राप्त होने पर ग्राम मनगटा में बिना वैधानिक अनुमति एवं नियमानुसार स्वीकृति के बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है। इसके बाद राजस्व विभाग की टीम द्वारा स्थल का निरीक्षण कर कार्रवाई की गई। बिना अनुमति कृषि भूमि का अवैध डायवर्सन एवं प्लाटिंग करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने कहा कि जिले में अवैध प्लाटिंग, अतिक्रमण एवं राजस्व नियमों के उल्लंघन के मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।

कई निवेशकों ने ली जमीन, सबकी प्लानिंग अवैध कारोबार

मनगटा में कई रिसोर्ट्स बन गए हैं, पर्यटन स्थल होने के कारण हजारों लोगों की आवाजाही होती है। व्यापारिक दृष्टि से भी यह उपयुक्त है। इस कारण कई निवेशकों ने यहां बड़े स्तर पर जमीनों का क्रय कर लिया है और यहां इसी तरह से नियमों को ताक में रखकर अवैध प्लाटिंग करने की प्लानिंग है। लेकिन अब जिला प्रशासन की इस सख्ती के बाद प्रशासन ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि क्षेत्र में आगे भी यदि किसी के द्वारा सक्षम अधिकारी के बिना अनुमति अवैध प्लाटिंग या शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण किया जाता है, तो उनके खिलाफ इसी तरह बिना किसी रियायत के सीधे बुलडोजर चलाने और कानूनी एफआईआर (FIR) दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी

इन खसरों पर की गई जिला प्रशासन ने कार्रवाई

मिली जानकारी के अनुसार 129/1, 137/1, 137/2, 130/1, 131/1, 147/1, और 157/1 पर निर्मित अवैध संरचनाओं को पूरी तरह ध्वस्त किया गया। इसी ग्राम में खसरा नंबर 565/1, 570/1, खसरा नंबर 569/1, खसरा नंबर 386/1, खसरा नंबर 628/1, इसके तहत ग्राम झुराडबरी खसरा नंबर 713/2, 722/2 खसरा नंबर 648/3 के खसरा नंबर 648/9 और 648/10 सभी कुल रकबा लगभग 150 एकड़ पर अवैध प्लाटिंग तथा अवैध कब्जा को हटाने की कार्रवाई की गई है।

पेट्रोल-डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, ग्राहकों को बांटी गई झाड़मुड़ा

भिलाई-3। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा भिलाई-3 में अनोखा प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पहुंचकर तख्तियों और बैनरों के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल भरवाने पहुंचे लोगों को प्रतीकात्मक रूप से झाड़मुड़ी वितरित कर महंगाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा है। बढ़ती महंगाई ने मध्यम वर्ग, मजदूर, किसान और छोटे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया है। ईंधन की कीमतें बढ़ने से रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी परेशान है। जिला ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का खामियाजा देश की जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि से लोगों का घरेलू बजट बिगड़ गया है। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज को मजबूती से उठाती रहेगी और महंगाई के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। ब्लॉक अध्यक्ष श्रीकांत वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता से अच्छे दिनों का वादा किया था, लेकिन आज हर वर्ग महंगाई से त्रस्त है।

उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के हित में लगातार सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे है और आगे भी यह विरोध जारी रहेगा।

करोड़ों की नहर में खेल: शुरुआत से ही 'संकरी सोच', भविष्य की तारीख में शुरू हुआ काम, पहली बारिश में बहने की आशंका

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले पंडरिख विकासखंड के अपर - आगर व्यापवर्तन योजना के शीर्ष कार्य एवं नगरों का कार्य संरचनाओं का जीर्णोद्धार कार्य में 5 करोड़ 30 लाख 80 हजार रुपये की लागत से बन रही नहर परियोजना अब गंभीर सवालों के घेरे में है। निर्माण स्थल पर लगी शासकीय सूचना पट्टिका खुद ही पूरे मामले की पोल खोलती नजर आ रही है। एक ओर कार्य लगभग पूर्णता की ओर बताया जा रहा है, वहीं बोर्ड पर कार्य प्रारंभ तिथि 03 नवंबर 2026 दर्ज है, जबकि वर्तमान समय मई 2026 चल रहा है। यानी कागजों में काम भविष्य में शुरू होना है, लेकिन जमीन पर लगभग खत्म होने की स्थिति में है। यह विरोधाभास केवल लापरवाही नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की कार्यप्रणाली पर सीधा संकेत देता है। स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारियों के अनुसार नहर निर्माण की शुरुआत में ही गंभीर तकनीकी खामियां दिखाई दे रही हैं। नहर का प्रारंभिक हिस्सा संकरा बनाया गया है, जबकि आगे जाकर उसे चौड़ा कर दिया गया है। तकनीकी जानकारों का मानना है कि यदि शुरुआत में ही पानी का प्रवाह सीमित कर दिया जाएगा तो बाद में नहर को चौड़ा करने का कोई व्यावहारिक औचित्य नहीं रह जाता। पानी की आपूर्ति की क्षमता वही रहेगी जो शुरुआती हिस्से की चौड़ाई तय करेगी। ऐसे में आगे चौड़ा निर्माण केवल बजट खपत का माध्यम प्रतीत होता है।

डिजाइन और क्रियान्वयन के बीच तालमेल की कमी स्पष्ट दिखाई देती है। यदि शुरुआत संकरी है तो अंतिम छोर तक पानी की उपलब्धता पर सीधा असर पड़ेगा। किसानों को सिंचाई सुविधा देने के नाम पर बनाई जा रही यह नहर वास्तविक लाभ देने के बजाय कागजी उपलब्धि बनने की दिशा में बढ़ती नजर आती है। निर्माण के दौरान एक और गंभीर लापरवाही सामने आई है। खुदाई से निकली मिट्टी को नहर से दूर हटाने के बजाय किनारे पर ही छोड़ दिया गया है। बरसात के मौसम में यही ढीली मिट्टी बहकर दोबारा नहर में जमा हो सकती है। इससे नहर की जलधारण क्षमता घटेगी और कुछ ही महीनों में नहर पुनः मिट्टी से भरने का खतरा पैदा हो जाएगा। जिस उद्देश्य से करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, वह पहली ही बारिश में प्रभावित हो सकता है।

वार्डवार अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी, सफाई, निर्माण, पानी और सौंदर्यीकरण पर फोकस करने निर्देश

नगर निगम आयुक्त ने बैठक लेकर अधिकारियों की नियुक्ति की

राजनांदगांव। शहर के वार्डों में मूलभूत सुविधा बिजली,पानी, सफाई के अलावा निर्माण कार्य तथा निगम द्वारा संचालित अन्य व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। असे लेकर नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने वार्डवार प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। नोडल अधिकारियो की बैठक लेकर उन्होंने अपने अपने प्रभारित वार्ड मे सुबह निरीक्षण कर व्यवस्था में सुधार हेतु कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने 51 वार्डों के लिए निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों को वार्ड सुविधाओं के सफल संचालन व क्रियान्वयन के लिए दायित्व सौंपा है। आयुक्त विश्वकर्मा ने कहा कि सभी नोडल अधिकारी अपने सहायक के साथ अपने प्रभारित वार्ड में सुबह निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान वार्ड में रोड, नाली की सम्पूर्ण सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के फलन, डोर टू डोर कचरा संग्रहण एवं सोर्स पर कचरा पृथकीकरण, एसएल आरएम सेन्टर वेस्ट प्रोसेसिंग कार्यों व वेस्ट टू कम्पोस्ट प्लांट सी एंड प्लांट के कार्यों का निरीक्षण-पर्यवेक्षण करना, वार्ड में जी.व्ही.पी./ सी.टी.यू. चिन्हांकित कर उसकी सफाई एवं सौंदर्यीकरण, सार्वजनिक एंव सामुदायिक शौचालयों का निरीक्षण एवं आवश्यक सुविधाए उपलब्ध कराना, शहर में स्वच्छता अभियान के तहत किये गये कार्यों का अवलोकन कराना है। इस प्रकार स्वच्छता संबंधी कार्यों का निरीक्षण कर व्यवस्था में सुधार की दिशा में कार्य करना है।

इन कामों में विशेष फोकस करने कहा

आयुक्त ने कहा कि साफ सफाई के अलावा पेयजल एंव विद्युत संबंधी कार्यो की नियमित पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना,गंदा पानी व कम पानी आने की शिकायत का निराकरण तथा अनावश्यक बहते नल को बंद करने संबंधी कार्य प्राथमिकता से करना है। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने वृक्षारोपण कर उसका संरक्षण करना है, वृक्षारोपण के लिए स्थल चयन करना है। साथ ही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एंव हेण्ड पंपो रिचार्जिंग संबंधी कार्यो के लिए भी निरीक्षण करना और बरसात में उसका क्रियान्वयन करना है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बीएलसी एवं एएचपी घटक अंतर्गत कार्यो की गुणवत्ता, समय सीमा पूर्ण कार्य करना एवं रिक्त आवासों को समय सीमा में आबंटन कार्य को प्राथमिकता देना है।

बारिश पूर्व तैयारियों का निरीक्षण, कसारीडीह नाला सफाई कार्य का लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर ने लिया जायजा

नालों की सफाई अभियान में तेजी, संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर

दुर्ग। आगामी बारिश के मद्देनजर नगर पालिक निगम प्रशासन द्वारा शहर में जलभराव और जल निकासी संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। महापौर अलका बाघमार एवं आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग एवं निगम अमला लगातार शहर की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहा है।

इसी क्रम में आज लोक कर्म विभाग प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर ने वार्ड पार्षद दीपक साहू, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता एवं सहायक स्वास्थ्य अधिकारी शेखर दुबे के साथ सहगल ऑटो के समीप कसारीडीह नाला पहुंचकर सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि बारिश के दौरान नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने एवं जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष तैयारी की जा रही है। जानकारी अनुसार शंकर नाला मुक्तिधाम के पीछे से सफाई अभियान प्रारंभ कर सुराना कॉलेज केलाबाड़ी नाला, पोटिया नाला सहित कसारीडीह नाला की व्यापक सफाई कराई जा रही है। साथ ही जलभराव संभावित स्थानों की पहचान कर वहां आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि निगम प्रशासन बारिश पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। शहर के प्रमुख नालों एवं जलभराव संभावित क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कहा कि बारिश के दौरान जलभराव एवं नाली जाम जैसी समस्याओं से निपटने के लिए नियंत्रण व्यवस्था भी बनाई जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में निगम की टीम नियमित मॉनिटरिंग करेगी तथा शिकायत प्राप्त होते ही तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण को लेकर निगम आयुक्त सख्त, अधिकारियों को दिए जल्द कार्रवाई के निर्देश

भिलाई-चरोदा। सुशासन तिहार के अंतर्गत आम नागरिकों से प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण को लेकर नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा के निगम आयुक्त दशरथ सिंह राजपूत ने निगम अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों में लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शिकायतों एवं आवेदनों का समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक के दौरान निगम आयुक्त ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए तथा प्रत्येक विभाग नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे। आयुक्त दशरथ सिंह राजपूत ने बैठक में कहा कि सुशासन तिहार शासन और प्रशासन के बीच विश्वास को मजबूत करने का माध्यम है। आम जनता की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान ही प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें ताकि नागरिकों को समय पर राहत मिल सके और शासन की योजनाओं का लाभ आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचे। बैठक में पेयजल, साफ-सफाई, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, राजस्व एवं अन्य जनसमस्याओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों पर विस्तार से चर्चा की गई। आयुक्त ने कहा कि निगम क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें।

शक्ति संवाद में शामिल हुई प्रियवंदा सिंह जूदेव महिलाओं के संरक्षण की दी विशेषज्ञों ने जानकारी

जूदेव ने कहा-महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता

जशपुरनगर। महिलाओं को यौन हिंसा से सुरक्षित करते हुए उन्हें कानूनी संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए श्रीनगर में तीन दिवसीय शक्ति संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों की महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य शामिल हुए। छत्तीसगढ़ से राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंवदा सिंह जूदेव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इस संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय साइंस और टेक्नोलाजी मंत्री जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। कार्यक्रम में महिलाओं को रोजमर्रा के काम के दौरान आने वाली कठिनाईयों को बताते हुए,इससे निबटने और इसके कानूनी उपचार के बारे में विशेषज्ञों ने विस्तार से जानकारी दी। विशेषज्ञों ने कहा कि जब तक जिम्मेदार लोगों को महिला संरक्षण के लिए बनाएं गए कानूनों की जानकारी नहीं होगी,तब तक ये कानून प्रभावी नहीं हो सकती। प्रियंवदा सिंह जूदेव ने कहा कि शक्ति संवाद कार्यक्रम में बहुत ही उपयोगी जानकारी मिली है। अब इस जानकारी के आधार पर जशपुर जिले में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होनें कहा कि महिला सुरक्षा और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाना केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। उन्होनें कहा कि जल्द ही जिले के एसएसपी डा लाल उम्मेद सिंह से मुलाकात कर,महिला सुरक्षा पर रणनीति बनाई जाएगी।

गैंदाटोला : शराबी कर रहे छात्राओं से बदतमीजी, महिलाओं ने अपने मायके भेजा बुलावा, करेंगे रायपुर पैदल कूच

मुख्यमंत्री निवेदन यात्रा आज से निकाली जाएगी, छह दिन में पहुंचेगी राजधानी

शराब दुकान खुलने से परेशानी, मुख्यमंत्री से मिलने ग्रामीण करेंगे पदयात्रा

राजनांदगांव। गैंदाटोला में शराब दुकान खोली गई। शुरू से ग्राम नुहाटोला के ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। खासकर महिलाएं परेशान हो गई है। इसका कारण भी बड़ा है, शराब दुकान में आने वाले लोग छात्राओं से बदतमीजी कर रहे हैं, कई महिलाओं के साथ ऐसा हुआ। इस कारण महिलाओं ने विरोध करने कमर कस ली है। अब वे मुख्यमंत्री निवेदन यात्रा निकालने का निर्णय ले चुकी है, इसकी शुरुआत 21 मई को गैंदाटोला से शुरू होगी जो छह दिन बाद रायपुर में समाप्त होगी। महिलाओं ने इस प्रदर्शन में अपने मायके वालों को बुलाया है, ताकि वे भी आए और शामिल हो। शराब दुकान खुलने से परेशानी महिलाओं ने बुधवार को पत्रकार वार्ता ली। यहां उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और विरोध का पूरा ब्यौरा भी दिया। महिलाओं ने बताया कि शराब दुकान खुलने के बाद से लड़कियों का उस रास्ते से आना-जाना मुश्किल हो गया है। एक वाकया भी बताया कि छात्राओं को शराबियों ने दौड़ा दिया था, जैसे-तैसे वे भागकर बची। इसकी जानकारी गांव प्रमुखों को दी, क्योंकि यह हिस्सा गैंदाटोला मे आता है, जबकि एकमात्र रोड है जो नुहाटोला और अन्य गांवों को जोड़ती है। इसलिए दूसरे गांव के लोगों को समस्या हो रही हे। इसी के चलते वे शराब दुकान को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग कर रहे है।

ग्रामीण 14 मई से कर रहे हैं प्रदर्शन

गैंदाटोला शराब दुकान का विरोध शुरुआती दिनों से चल रहा है। अभी ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और वे 14 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री निवेदन यात्रा निकालने की फैसला किया है। इसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शामिल होंगे। महिलाओं ने बताया कि 21 मई को गैंदाटोला से जोशीलभाठी, 22 मई को कुम्भी होते हुए डोंगरगांव, 23 मई को डोंगरगांव से राजनांदगांव, 24 मई को दुर्ग, 25 मई को कुम्हारी और 26 मई को कुम्हारी से राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल सीएम विष्णु देव साय से भेंट करेगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित 02 जून तक

दुर्ग। एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग-शहरी के अंतर्गत विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए महिला उम्मीदवारों से आगामी 02 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। परियोजना अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत ई-भर्ती पोर्टल के माध्यम से पूरी की जा रही है। इच्छुक एवं पात्र महिला अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल https://aww.e-bharti.in/ पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकती हैं। आवेदन करने के लिए आवेदिका को उसी वार्ड की स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, जिस वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र के लिए पद रिक्त है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायतीन क्षेत्र दुर्ग होगा। डाक पंजीयन क्रमांक- सीजी/दुर्ग/लोकतंत्र प्रहरी/2026-28, Email : loktantraprahrinews@gmail.com